Shri Ahmad Hossain Mondal for remaining absent from all meetings of the House during the 96th Session of the Rajya Sabha?

(No hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

I have also to inform Members that a letter dated the 8th May, 1976 has been received from Shri Bhairon Singh Shekhawat to the effect that leave of absence from attending the 96th Session of the House be granted to him on account of his detention.

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Bhairon Singh Shekhawat for remaining absent from all meetings of the House during the 96th Session of the Rajya Sabha?

(No hon. Member dissented.)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

RESOLUTION RE. DELETION OF "RIGHT TO PROPERTY" FROM, AND INCLUSION OF "RIGHT TO EMPLOYMENT" IN THE CONSTITUTION TO REGULATE ECONOMIC POLICIES IN ORDER TO REMOVE SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITIES AND CREATE MAXIMUM EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE COUNTRY

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :

> "इस सभा की सम्मति है कि आर्थिक नीतियों को इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं समाप्त हों और देश में रोजगार के अधिकतम अवसर दिये जा सकें और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह सभा सरकार से अनुरोध करती है वह भारत के संविधान से "सम्पत्ति के अधिकार" को निकालने और उसमें रोजगार के अधिकार को सम्मिलित करने के लिए उसमें प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाये।"

[Mr. Deputy Chairman in the Chair.]

उपसभापति जी, जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तभी उसने यह निश्चित कर लिया था कि हम इस देश का नियोजित विकास करेंगे, और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई जिसने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अपने लक्ष्य निर्धारित किए। आजादी आने के बाद भी, जब स्वराज्य आया, तो बापू ने जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने एक बात कही जो हमारी समस्त आर्थिक नीतियों का आधार है और होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वराज में हम "हरएक आंख के हर आंसू को पोंछ देंगे।" पण्डित जवाहरलाल जी ने आजादी के बाद योजनाओं के द्वारा, देश की पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, इस देश के विकास की आधारशिला रखी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारे देश पर कई तरह के ऐसे संकट आए जिससे, जिस दिशा में हमें जाना चाहिए था, हमारी जो आय के स्रोत थे उनको जिस तरफ हमें लगाना चाहिए था उससे दूसरी तरफ मजबूरन हमें आय के स्रोत लगाने पड़े चाहे वह 1962 में चीन के साथ युद्ध हो चाहे सन् 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चाहे फिर बांगलादेश के लिए जो लड़ाई लड़ी गई 1971 में, वह हो; उसके कारण हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर जो धन खर्च होना था जिससे हमारे देश का विकास हो सकता था, उसमें कमी आई। इसके बावजूद यह सही है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के सही परिणाम आए हैं जिनके फलस्वरूप हमारे देश में एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, टेक्निकल क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं; और आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि आज जितनी हमारी आणविक शक्ति है उसमें हम विश्व के छः देशों में से एक हैं, अंतरिक्ष में हमारे यहां आर्यभट्ट है। हम गौरवपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में हमने प्रगति की है। लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरे दृष्टिकोण से भी हमें अपनी इन योजनाओं को देखना होगा।

[श्री नत्थी सिंह]

अभी जो हमारा बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भी इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि इन योजनाओं के द्वारा जो हमारा लक्ष्य है गरीबी हटाओ उसके कितने नजदीक हम पहुंचे हैं, कितना गरीबी को हटा पाए हैं? पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य यह भी था कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, हर आंख का आंसू तभी पोंछा जाएगा जब हर व्यक्ति को रोजगार मिले और 5 न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों--रोटी की, कपड़े की, मकान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। ये न्यूनतम आवश्यकताएं उनकी पूरी हों। तो जब हम अपनी योजनाएं चलाएं तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम इन क्षेत्रों में कहां तक आगे बढे हैं। इस स्थिति में एक बात तो बिल्कुल हमारे सामने है। आज भी यह एक सर्वमान्य सत्य है कि हिन्दुस्तान के 20 करोड़ आदमी गरीबी की न्यूनतम सीमा रेखा से नीचे रहते हैं और आज 75 परिवार इस देश में ऐसे हैं जिनके लिए हम कहते हैं वे हिन्दुस्तान की 40 प्रतिशत दौलत के मालिक हैं। यह स्थिति जब रहती है तो निश्चित रूप से हमने अपनी योजनाओं में ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा जिससे वह स्थिति बदले, खास कर जब हम देखते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में जहां तक रोजगार की स्थिति है वह रोजगार की स्थिति क्या रही है। उपसभापति महोदय, इस संबंध में मैं आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा जो एक कमेटी बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट की तरफ दिलाऊंगा—रिपोर्ट आफ दी कमेटी आफ एक्सपर्टस आन् अनइम्प्लायमेंट एस्टीमेट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार, जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं थे लेकिन ऐसा लगता है कि 30 प्रतिशत आबादी बेरोजगार थी। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उस वक्त, उन्होंने कहा है 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। उसके बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो उनका कहना है उस वक्त 90 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। जब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो कहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या 90 लाख और 1 करोड़ के बीच हो गई। इन योजनाओं में जो रोजगार में नहीं है या जिनके पास एक तरह से जीविका के साधन नही हैं, उसकी भी स्थिति यह है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत में हमारा बैकलाग था 1 करोड़ के करीब। उसको भी हम देखें तो आज जो हमारे इम्प्लायमेंट एक्सचेजेज में बेरोजगारों की सूची दर्ज है, उसमें ग्रामीण बेरोजगार, जो कि हमारी आबादी का 80 प्रतिशत है, उनका कोई लेखा-जोखा नही रहता। उनकी जो स्थिति है वह एक सवाल के जवाब मे बताया गया है, 31 जनवरी 1975 को। इम्प्लायमेंट एक्सचेजो में रोजगार पाने के लिए जिन लोगों ने नाम अंकित कराए थे उनकी तादाद 84 लाख 98 हजार थी।

हमारे यहां जो इकोनौमिक सर्वे आफ इंडिया प्रकाशित होता है उसमे पेज 13 में दिया गया है कि 31 सितम्बर 1975 को इन बेरोजगारों की तादाद जो इम्प्लायमेंट एक्सचेजो में दर्ज थी वह 92 लाख 54 हजार थी इसके बाद पहली जनवरी 1976 को एक सवाल के जवाब में जो 29 अप्रैल को लोक सभा में दिया गया था, उसके अनुसार जो तादाद 31 सितम्बर 1975 को थी वह 92 लाख 54 हजार थी और यह तादाद पहली जनवरी 1976 को 93 लाख 97 हजार हो गई। इस बीच जो रोजगार दिया गया या कुल रोजगार जो एम्प्लायमेंट एक्सचेजों के जरिये प्राप्त हुए उनकी तादाद पूरे वर्ष में 2 लाख 25,115 है। इस तरह से हम देखते हैं कि केवल एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में जो नाम दर्ज हैं, उनकी तादाद करीब 96 लाख बेरोजगारों की है। स्थिति यह है कि जो चौथा प्लान है उसमे करीब एक करोड़ बेरोजगार आज एम्प्लायमेंट एक्सचेजों में दर्ज थे और इस तरह से बेरोजगारों की संख्या करीब 1 करोड़ के लगभग है। एक करोड़ बेरोजगारो में से करीब दो लाख या ढाई लाख तक के लोगो को रोजगार दे पाये हैं। इस तरह से हमारी योजनाएं किस तरह से तरक्की कर पायेंगी और किस तरह से हम समस्या का समाधान कर सकेंगे, इस बात पर हमें निश्चित रूप से सोचना होगा।

एक दूसरा सर्वे जो किया गया है और उस सर्वे के अनुसार यह बतलाया गया है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष काम करने योग्य कितने व्यक्ति होते हैं ? अगर हम 18 से 21 वर्ष की आयु के लोगों को लें, तो प्रतिवर्ष हिन्दस्तान में 50 लाख और 60 लाख के बीच ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनको रोजगार चाहिये । इसका मतलब यह होता है कि प्रतिवर्ष 50 या 60 लाख लोग ऐसे व्यक्ति होते है जिन्हें हमें रोजगार देना चाहिये । अगर हम काम करने योग्य उम्र को 14 साल मानकर चलते हैं, तो जो 50-60 लाख की तादाद है बेरोजगारों की वह और भी अधिक बढ़ जायेगी और इस तरह से बेरोजगारों की तादाद पहली संख्या से भी ज्यादा पहुंच जाती है ।

उप-सभापति जी, मै आपका ध्यान इस सबध में इस ओर दिलाना चाहता हू कि जब कभी आप गांव में जायें, चाहे मंत्री महोदय जायं, प्लानिंग मत्री पद यात्रा में जाये--जैसा कि हम हम सब लोग पद यात्रा कर रहे हैं--तो अक्सर गाव वाले दो सवाल किया करते है। एक सवाल तो वे अनाजों के भावो के सबध मे करते है और दूसरा सवाल नौकरी के सबध में करते हैं । एक आदमी जो सन् 1952 से वोट देते चला आ रहा है, वह 25 साल के बाद पूछता है कि हमारे लिए रोजगार की क्या व्यवस्था की गई है । इसके लिए कोई जवाब संभव नही हैं और न ही कोई दूसरा जवाब दिया जा सकता है । इस तरह की दयनीय स्थिति हमारी हो गई है । इस स्थिति को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिये क्योंकि प्रतिवर्ष 50-60 लाख लोग नौकरी के योग्य हो जाते है । उसी सर्वे मे हमें यह भी बतलाया गया है कि 15 लाख व्यक्ति ऐसे है जो संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने के काबिल हैं और उन्हें रोजगार संगठित क्षेत्र में दिया जाना चाहिये । 35 लाख आदमी हर साल ऐसे तैयार हो जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार देने की आवश्यकता है।

उप-सभापति जी, मैं यह कहने में कतई गुरेज नहीं करता हूं कि हिन्दुस्तान का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वह पूरे का पूरा बेरोजगार क्षेत्र है। हमारी यह मान्यता रही है कि 6 एकड़ से नीचे जिस के पास जमीन है उसे अन-इकोनौमिक होल्डिंग मानी जाती है । इतनी जमीन जो लोग अपने पास रखते हैं वे बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर पाते हैं। दो तीन प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे कुछ ज्यादा जोत हो सकती है। इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसकी संख्या करीब 96-97 प्रतिशत है, वह साल में बेरोजगार या अर्द्ध बेरोजगार की स्थिति में रहता है । अब जो 15 लाख को संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की बात है, उनकी स्थिति क्या है ? उनके सबंध में जो रिपोर्ट है उसमें बतलाया गया है कि पब्लिक सेक्टर या आर्गनाइज्ड सेक्टर मे नौकरियों की जितनी क्षमता है, वह करीब साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार देने की है । इसके नीचे जो लोग बाकी बच जाते है, उनको कितना रोजगार दिया गया है, वह इस रिपोर्ट मे बतलाया गया है । 1973 मे जो संगठित क्षेत्र था चाहे वह पब्लिक सेक्टर की नौकरी हों या सरकारी नौकरी हों, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा था, उनके लाभों की क्या स्थिति थी, इसके सबंध में मै आपका ध्यान रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि सन् 1973-74 में जो इनका आधारभूत लाभ था उसमे 101 परसेंट की वृद्धि हुई है और जो आपरेशनल प्राफिट है वह तिगुना हो गया है । जब कि निजी उद्योगों में इस तरह का प्राफिट हो रहा है, इस तरह का लाभ हो रहा है, परन्तु हमारी जो रोजगार देने की क्षमता है वह कुछ भी नही बढ़ी है। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से विचार करना होगा कि आज जब हम यह कहते है कि 15 लाख मे से केवल साढ़े तीन लाख लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे पायेंगे तो इस पचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गये है उनकी पूर्ति कैसे होगी ? बेरोजगारों की समस्या फिर किस प्रकार हल होगी, इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना होगा ।

जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से विचार करना

[श्री नत्थी सिंह]

होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम सरकार के ऊपर जोर डालें कि इसका निदान इस तरह का हो जिससे रोजगार देना उसका एक ऐसा कर्त्तव्य बने, जिससे वह बच के न निकल सके । जब यह आधार हमारा होगा तभी सरकार अपनी योजनाओं के आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बात सोचेगी। तो मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है इसके संबंध म हमें विचार करना ही होगा । हमने देखा कि निजी क्षेत्रों को राहतें दी गई हैं । निजी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वह रोजगार दे नहीं सकता । अब हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं । उसके संबंध में जो सर्वेक्षण हुआ, एकानामिक सर्वे हुआ एकनामिक सर्वे आफ इंडिया द्वारा, उसके अनुसार जितनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, रिफार्म होते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि जो लोग काम में लगे हुए हैं, फैक्टरीज मे लगे हुए हैं उनके लिये तमाम सुविधायें हो जाती हैं, उनके लिये आराम हो जाता है लेकिन उसका दूसरा परिणाम यह होता है कि नये रोजगार के दरवाजे बन्द हो जाते हैं । यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा मे सोचना पड़ेगा और हमें अब यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गये है कि जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान द्वारा दिये गये हैं, उन पर हम दूसरी तरह से नजर डाले । आज तक हमने सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों मे माना है । मेरा कहना यह है कि यह भी एक कारण है, बड़ा कारण है, जिस से हमारी दिशा, हमारे दृष्टिकोण को बदलने मे सहायता मिली है ।

यह जो आजादी हमारी आई है, हमारे देश में आई है, उपसभापति महोदय, यह सही है कि इस आजादी के लिये बहुत भारी बलिदान किये गये, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दीं, बहुत संघर्ष किये और उसके बाद हमें आजादी मिली है । लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि आजादी समझौते की आजादी भी थी और जब हमको समझौते से आजादी मिली तो हमें कई बातों पर समझौता करना पड़ा । जो प्रापर्टी का राइट हमको मिला, जो प्रापर्टी का अधिकार हमें मिला है, वह उन समझौतो में से एक है । हमने जो समझौते उस वक्त किये थे उन पर पुनर्विचार किया । चाहे वह राजाओं के प्रिवी पर्स का समझौता हो, चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे आई०सी०एस० आफिसरों को दी जाने वाली सुविधायें हो, इन सवालों पर हमने पुनर्विचार किया है और पुनर्विचार के बाद हमने उन सुविधाओं को वापस लिया है । इसी तरह से संपत्ति का अधिकार है, जिसको अक्षुण्ण रखने के लिये सरकार ने इजाजत दी है परन्तु जब सरकार उसके बारे में कानून बनाती है तो उसमें इस तरह की स्वतंत्रता नही होती और कहा जाता है कि हमारे मूलभूत अधिकारो का हनन किया जा रहा है । जितनी बार हमने संविधान में संशोधन किये हैं, लेड रिफार्म की बात कही है, जमीन की सुधारों की बात कही है, इन सुधारो को लेकर ही लोग बराबर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गये हैं ।

सम्पत्ति के मौलिक अधिकारो के संबंध में कुछ लोग कहते है कि डेढ़ सौ रुपया पाने वाला गरीब आदमी जो पोस्ट आफिस मे जमा कराता है , वह भी उसका सम्पत्ति का अधिकार है और उसके इस अधिकार को आप क्यो छीनना चाहते है । मै आपसे कहना चाहता हूं कि इस अधिकार का फायदा किसने उठाया है । क्या उस आदमी ने जिसके पास डेढ़ सौ रुपये की आमदनी है या जिस की डेढ़ सौ रुपये की सेविंग है उसको कुछ फायदा मिला है या उन लोगों को फायदा मिला है कि जो पूरे देश में 75 परिवार हैं और जिन का देश की 40 प्रतिशत दौलत पर कब्जा है। अगर उस का फायदा उन लोगो को मिला है जिन्होंने देश की चालीस प्रतिशत दौलत पर कब्जा कर रखा है तो हमे निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना होगा और हम को संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारो में से निकालना होगा और रोजगार को मूलभूत अधिकारो में शामिल करना होगा ताकि सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाये बनाये जिस में सब को रोजगार मिल सके और नही तो उस को लोगों

को बेरोजगारी का भत्ता देना पड़े । तभी हमारा दृष्टिकोण इस दिशा में सही बन सकता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आप देखें कि आज स्थिति क्या है । आज स्थिति यह है कि आज एक आदमी खेती भी करता है, वह आदमी वकालत भी करता है और वह आदमी बिजनेस भी करता है । वही आदमी पार्लियामेंट का मेम्बर भी हो सकता है और उस के साथ और दस धंधे कर सकता है । उस के लिये कोई पाबन्दी नही । और दूसरी तरफ बीस करोड़ आदमी ऐसे हैं कि जो गरीबी की न्यूनतम सीमा रेखा के नीचे रहते हैं । जिन को कोई रोजगार मयस्सर नहीं है । तो इन दो स्थितियों में हम को तुलना करनी पड़ेगी कि क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन निरीह लोगों को छोड़ दें कि जो इस देश के असली नागरिक हैं । अगर हम उन को छोड़ना नहीं चाहते तो हम को निश्चित रूप से एक बात करनी पड़ेगी और अपने देश में इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस मे एक आदमी को एक ही रोजगार हो, उस से अधिक नहीं और उस में उन को पेट भरने लायक दाम मिलना चाहिए । आज तो हमें न्यूनतम आवश्यकतायें चाहिए । जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उन को पूरा करना है । लक्जरीज नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए । उन को तो आज कपड़ा मिल जाय, रोटी मिल जाय, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल जाय । यदि हम उन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तभी हम देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे । आज की जो अर्थ-व्यवस्था है उस में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का अपर हैंड है । जिस आदमी के पास पैसा है, जिस के पास साधन है उस की छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाये । लेकिन जिसके पास पैसा नही है, जिस के पास श्रम शक्ति है, जिस के पास केवल उस के हाथ पैर हैं उस को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये सुविधायें नही मिलती । इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमतायें भी है । आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है जिन के बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं । पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और आई० ए० एस० के इंतहान में बैठते हैं, छोटे आदमी के बच्चों की वहां तक पहुंच नहीं होती । इसलिये संपत्ति के अधिकार को निश्चित रूप से मूलभूत अधिकारों में से निकालना पड़ेगा । लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं । जब मैं यह बात कहता हूं तो यह भ्रम पैदा हो सकता है कि क्या हम पूरी तरह से संपत्ति की समाप्ति की ओर जा रहे हैं या कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं जहां सारी संपत्ति राष्ट्र की ही होती है । मेरा कोई ऐसा मंशा नही है । सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी । भूमि संपत्ति पर ही नहीं, शहरों की जमीन पर ही नही, सारी संपत्ति पर, चाहे वह कारखानों से पैदा हो या अन्य रोजगारों से, हमें सारी संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी कि इतने से अधिक एक आदमी संचय नही कर सकता और जब हम यह सीमा लगायेंगे तो मूलभूत अधिकारों में से सपत्ति को हटा कर उसे डाइरेक्टिव प्रिसिपल्स में रख दीजिए जो जस्टिसेबिल न हो और रोजगार के राइट को फंडामेंटल राइट्स में ले आइये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । एक छोटा तबका है जो संगठित क्षेत्र में रोजगार पाता है जिस को एजूकेटेड कहते हैं । यह थोड़ा एजूकेटेड यह तबका होता है । लेकिन बहुत बडा तबका ग्रामीण क्षेत्र का है, जहा 80 प्रतिशत हमारी आबादी है और जिस के प्रति हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस सदन में और दूसरे सदन में भी माना कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं राष्ट्र की आमदनी के उस में से 55 प्रतिशत देश के बीस प्रतिशत लोगों पर खर्च होता है जो कि शहर में रहते हैं और 45 प्रतिशत उन लोगों के ऊपर खर्च होता है जो गांवों में रहते है और जिन की आबादी 80 प्रतिशत है । तो यह कब तक चलेगा । आज गाव का आदमी मैट्रिक पास कर के शहर की तरफ भागता है । अगर बेरोजगारी मिटानी है तो गांव वालों में यह समझ पैदा करनी होगी कि उन में शहर के प्रति जो ललक है वह उन को छोड़नी चाहिए । वहां हम को बिजली की, पानी की सुविधा देनी होगी ताकि लोग वही रहे । तो यह जो प्लानिंग हम करते हैं उस में हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जितनी दौलत है, जो हमारे पास है उस में से कम से कम उस का दो तिहाई भाग केवल खेती पर, सिंचाई पर, बिजली पर और गांवों की सड़कों पर खर्च किया जाय ताकि गाव इस तरह के बनें कि जिस में लोगों में शहरों में जाने की आकांक्षा जो है वह बलवती न रहे । गांवों में बड़े उद्योग धंधे हम खोलें । जो उद्योग धंधे हम ने लगाये हैं वह अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन

[श्री नत्थी सिंह]

अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ग्रामीण उद्योग धंधे मे बढ़ोत्तरी करें क्योकि केवल खेती पर मुनहसिर रह कर आदमी स्वावलम्बी नही हो सकता। आज सब खेती की पैदावार के भावो का सवाल आता है तो सदन में इस पर कई बार चर्चा भी हुई है और मैं ने भी कहा है कि जो लागत आती है उस पर किसान की वह भी उसकी वापस नहीं मिल पाती। इस आर्थिक समीक्षा में भी है कि हमने पिछले दिनों बहुत बड़ा प्रयास किया और इस देश में जो भयकर महंगाई थी, बड़ी भारी मुद्रा-स्फीति थी, काला-बाजारी थी, उस सब पर अकुश लगा है। उसको रोकने में हम सफल हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका है। कितने कारखानों मे बनने वाली चीजों के दाम गिरे हैं। खाद्यान्नों की कीमतें गिरी है, उसका ननीजा यह हुआ है कि किसानों को दाम कम मिले, लेकिन किसान को जो चीज चाहिए कारखानों में बनने वाली, उसमें गिरावट नही आई। इसलिए हमको यह सोचना पडेगा कि मुल्क मे एक दाम नीति तय हो। चाहे कारखाने मे बनने वाली चीज हो, चाहे खेत मे पैदा होने वाली चीज हो, उसमें क्या लागत लगती है और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए जो कि उपभोक्ता को मिले। यह आवश्यक काम है जिसको करना पड़ेगा नही तो खेती करने वालों को मुश्किल हो रही है। 105 रुपए क्विंटल आपने गेहूं का दाम कर दिया। एफ० सी० आई० वाले लेते हैं नहीं। जब एक तरफ यह हालत हो रही है, दूसरी तरफ 1973 के बाद निजी कम्पनिया एक आदमी को भी रोजगार नही दे पा रही है, उनको 101 प्रतिशत मुनाफा प्राप्त हो रहा है। इसे बदलना पड़ेगा। इसलिए मै आपको कहना चाहूंगा कि यह जो सबसे बड़ा सैक्टर है उसकी ओर ध्यान दें। ये जो हमारे रोजगार वाले हैं, नौकरी वाले है, कलम से जो खेती लगाते हैं, कोई रचनात्मक काम नही करते, मेहनत नही करते, कोई उत्पादक काम नही करते, कलम से कागज पर खेती करते है, यह स्थिति जो है यह चलेगी तो देश को जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं, देश उस दिशा में नहीं चलेगा। गांवों में डाक्टर भेजो तो मना करता है, वह कोशिश करता है कि गांवों के बजाय शहर मे पोस्टिग हो जाए। मै कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इसलिए बहुत जरुरी है कि हम उधर जायें।

आज हम जमीन मे ज्यादा पैदावार बढ़ाने की बात करते है। इस सदन में भी और उस सदन में भी बराबर यह बात कही गई कि अगर हम ग्रामीण लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो भूमि सेना बनायें। जो हमारे चंबल रेवाइंस है, जहा डाकू लोग जनता को लूटते हैं, लोगो को भर्ती करके वहां पेड़ लगाये जाए। लोगो को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की जो सम्पत्ति है उसका प्रयोग कर सकेंगे।

आज देश में इस बात की चर्चा है कि सब जगह वृक्षा-रोपण होना चाहिए। आज भी हम जो बरसात पर मुनहसिर है, उससे वंचित न रह जाये। हम क्यो नही इस तरह की वन सेना बनायें ताकि लोगो को रोजगार में भी लगा सके और वन सम्पत्ति की वृद्धि कर सके।

खेती आज पानी के लिए तरसती है। आज भी सिचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। हमें अपनी योजनाओं में यह निश्चित रूप से तय करना होगा सारे देश को एक मानते हुए कि सारे देश की जमीन को पानी मिले और पानी के लिए हमें अधिक से अधिक पैसा देना चाहिए और सब कामों पर ब्रेक लगायें लेकिन खेती योग्य जमीन जो पड़ी है उसको खेती के लायक बनाकर उसमें खेती करें। फारेस्ट लगाये, सिचाई का प्रबन्ध करें, बिजली का उत्पादन बढ़ाये तो निश्चित रूप से हमारे गांवो में रोजगार के साधन पैदा हो सकेंगे। उसके बाद ही यह स्थिति पैदा होगी कि हम देश में बेरोजगारी को हटा सके। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो विद्यार्थी कालेजों में पढ़ते हैं उनको हम गांवों की ओर आकृष्ट कर सकेंगे। इसके लिए हमें शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, उनके दिमाग और दिलो को बदलना पड़ेगा। अब श्रम से कतराने वाली बात नही चलेगी। हम अपने पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से वह बात बनायें तब काम चलेगा। आज जो हमारे शिक्षा के मन्दिर बने हुए है उनको हमें बदलना पड़ेगा और हमें सोचना होगा कि संवैधानिक तौर पर हम किस तरह से उन लोगों को इस तरफ ले जाये जिससे हमारे देश की समस्याओं का वह समाधान कर सकें। एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि हमने न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया। इसमें हमने व्यवस्था की है कि एक व्यक्ति को कम से कम 5 रुपए मजदूरी मिले लेकिन वह भी उनको नही मिलती है। दूसरी तरफ जो सार्वजनिक क्षेत्रों

में काम करने वाले लोग है जैसे एल० आई० सी० के बड़े-बड़े आफिसर, आई० ए० सी० और दूसरे कारपोरेशन के बड़े-बड़े आफिसर है उनके वेतन देखिए। दोनो मे जमीन आसमान का अन्तर है। मैं जानना चाहता हू इतना अन्तर क्यों? हम अभी तक इस चीज को बर्दाश्त करते आए है योजना को आधार बना कर। यह जो हमने सम्पत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार बना रखा है यह गलत है। हम इसी कारण इस विषमता को सहन करते आए है। अब हमें इस विषमता को दूर करने के लिये अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमारे संविधान मे जो सम्पत्ति को मूलभूत अधिकार माना गया यह अक्षुण्ण है इसकी जगह हमें श्रम को मानना होगा। हमे रोजगार के अधिकार की तरफ भी ध्यान देना होगा।

एक बात मै यह कहना चाहता हूं कि हम पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रहे हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि सबसे ज्यादा लोग जिस रोजगार पर मुनहसिर हैं वह खेती का रोजगार है। खेती के रोजगार में भी ज्यादातर लोग जोतो पर मुनहसिर रहते हैं। इसमें उनको 5 रुपए भी वेतन नही मिलता। मैं कहना चाहता हूं हम जमीन की अधिकतम सीमा कायम करे। मै इसका समर्थक हूं। इसे जरूर किया जाना चाहिए।

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार): दृष्टिकोण कैसे बदलना पड़ेगा जरा इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री नत्थी सिंह: जैसे हम और आप बैठे है। हम लोग यहां बैठ कर ही दृष्टिकोण बदल सकते हैं। ह्विप की परवाह न करके अपनी बात जो सही हो सदन मे रखे। मै समझता हूं तभी दृष्टिकोण बदल सकता है। शास्त्री जी ने जो बात कही उसका उत्तर मैं इस तरह भी देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज यहां पर राज कर रहे थे उनके बारे में हम नही सोचते थे कि वे कभी चले जाएंगे लेकिन वे चले गये। 1942 में उन्होंने क्या नही किया, क्या-क्या अत्याचार नहीं किये लेकिन हमने उन सब को सहन किया और उनको यहां से धकेला। दृष्टिकोण बदलने का अधिकार अब तो हमारे ही हाथ में है। हम दो-तिहाई बहुमत से यहां बैठे हुए हैं और लोकसभा में भी हमारा दो-तिहाई बहुमत है। यहां बैठ कर हम मूलभूत अधिकारो में परिवर्तन कर सकते है। केवल जरूरत है दृढ़ आस्था की, दृढ़ निश्चय की। इसको कायम करने में आप जैसे बुजुर्ग लोग जो शोषण के शिकार रह चुके है उनको अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत पैदा करनी होगी।

दूसरी बात जो मैं कह रहा था, खेती के संबंध में कह रहा था। हम अधिकतम सीमा रेखा तय करें यह बिल्कुल सही बात है—चाहे 10 एकड़ की सीमा हो या 15 एकड़ की। यह हमे अपने आर्थिक आधारों पर करनी चाहिये। इसके साथ-साथ अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी मिटे, अर्ध बेरोजगारी मिटे तो हमें जमीन की न्यूनतम सीमा रेखा भी तय करनी होगी। उसमें हमें यह करना होगा कि इतने से कम जमीन नही होगी, इतने से कम जमीन पर बटवारा नही होगा या इतने से कम जमीन एलाट नही होगी। आजकल लोगों को अपनी मेहनत भी वापस नही मिलती है। इसमें भी उनको काफी दिक्कते उठानी पड़ती हैं। हम उनको एक बीघा या दो बीघा जमीन दे कर खुश कर देते हैं भले ही उसमें कुछ भी पैदा न हो सकता हो। यह जो हमारी नीति है इसको हमें बदलना होगा। जमीन को भी हमें एक मुनाफे का धंधा बनाना होगा और जो उसकी मेहनत लगे उसकी मेहनत तो वापिस करनी ही होगी। जहां हमने हाइयेस्ट सीलिंग लैंड तय की है वहां हमे लोएस्ट सीलिंग लैंड भी तय करनी होगी। हम तभी बचा सकते है जब हम गावो मे रहने वाले लोगों को दूसरे रोजगारो की सुविधाएं भी दें। अगर हम ऐसा नही करेंगे तो भूखा और भूखा हो जाएगा।

दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूं वह यह कि लैंड रिफार्म में कुछ कमियां रही हैं। शहरो मे जो सम्पत्ति है उस पर प्रतिबन्ध लगाने की बात तो हम बहुत करते है लेकिन लगा नही पाते। यह इसलिये नही लगा पाते क्योंकि कोई न कोई कारण पैदा हो जाता है। सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध हम कई कारणों से नहीं लगा पाते। इसके लिये मूल रूपरेखा मैने तैयार की है जो मेरे प्रस्ताव में है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारो की सूची से हटाया जाय और उसमें रोजगार के अधिकार को जोड़ा जाये। हमारे देश में आज भी आप देखेंगे कि कुछ लोग बड़े-बड़े आलीशान एयर कन्डीशन्ड मकानों में रहते है। जब कुछ लोग शहरों के अन्दर बड़े-बड़े मकानों मे रहेंगे तो

[श्री नत्थी सिंह]

फिर अन्य लोगों को स्थान कहां मिलेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस तरह से परती जमीन को काम में लाने के लिए आज भू-सेना बनाने की आवश्यकता है और जंगलों के संरक्षण और उनके उपयोग के लिए वन-सेना बनाने की आवश्यकता है उसी तरह से शहरों के अन्दर भवन-सेना बनाने की आवश्यकता है। शहरों के अन्दर बड़े-बड़े लोग जिस तरह से आलीशान भवनों में रहते हैं उनके लिए भी एक स्टेन्डर्ड फिक्स किया जाना चाहिए कि उन्हें तीन कमरों के फ्लेट में रहना होगा और बाकी स्थान सरकार को देना होगा। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जब तक हम पक्के इरादे के साथ कोई काम नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से विषमता दूर नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं हैं उन पर एक बार फिर गम्भीरतापूर्वक नजर डालने की जरूरत है और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हमारा दृष्टिकोण सम्पत्ति परक न होकर श्रम परक होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संविधान से सम्पत्ति के अधिकार को हटाया जाये और रोजगार के अधिकार को उसमें स्थान दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.45 P.M.

The House then adjourned for lunch at twelve minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-six minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Lokanath Misra)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): Shri Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very glad that the hon. Member, Shri Nathi Singh, has taken the trouble of moving a Resolution of this kind. We are entirely in agreement with the intentions as well as the contents of the Resolution. Unfortunately, however, the party to which he belongs is not taking the necessary steps to see that such a Resolution is implemented, although there are declarations which should justify the implementation of a Resolution of this kind. Sir, we are in the tenth month of the emergency and it was expected that the emergency would be utilised in order to weaken the socio-economic base of the rightist and the reactionary forces. In fact, Prime Minister Indira Gandhi herself assured the House and also the nation that following the Twenty-Point Programme, more programmes would come. Today it is time to review what has happened to the Twenty-Point Programme and how exactly it is being implemented by those who are supposed to take greater initiative than the others for the implementation of the Twenty-Point Programme. Now, Sir, we have some experience having gone round the villages in different parts of the country. Perhaps you are aware that the guided Samachar, that is to say, the present news agency guided by some visible and invisible people, cannot give publicity to what is being done by people belonging to Opposition or even to the Congress Party unless this has the approval of some people somewhere. We find that the land reforms are not being implemented and that in many places the declarations that are made about the implementation are not true and correct and are not borne out by actual facts. For example, in West Bengal we find that the minimum wage for the agricultural labour which is fixed at a high rate of Rs. 8/- per day, has not at all been implemented anywhere in the State. Most of them are given even less than Rs. 4/- and women are paid still less. Now, I should like to know from the Government when laws are passed laying down the minimum wages, whose responsibility it is to ensure the implementation of such laws. Surely, it is the responsibility of the Government to see that the agricultural wage which has been fixed by it is implemented.

This is not being done and this can be said about other States also. Our information is that in most of the States the minimum wage for agricultural labour, whatever is fixed under the law, is being flouted by the landlords and other elements with the Government simply looking on and, in some cases, directly helping. Well, I know of a case in Malda, for example, where an agricultural worker was threatened with punishment and imprisonment because he demanded and stood for the minimum wage for the agricultural labourers. I can cite some examples. House sites are supposed to have been given. Well, in some places, undoubtedly they have been given. But we cannot go by the declaration any more. Having gone to the villages, our comrades and friends are finding that house sites had not been allotted at all. I have with me a list of people who are supposed to have been given *pattas* but who have not, in fact, got any *pattas*. In many places, *pattas* of lands are being given to people who do not live in the villages.

Sir, it is said that in West Bengal, the JLROs are making a lot of money. Sir, the policemen seem to be complaining that in the past they stood first in the category of people who used to take bribe, and now their place has come down to the fourth. First, the JLRO, then the BDO, then the irrigation people, and then, we are told, comes the traditional bribe-taker, the Police. It is not I who am saying it. It is they who are saying it. In many places drinking water is not there, irrigation water is not there, and other arrangements are not there. Now, Sir, the money-lenders, for example. Loans from these usurious money lenders are to be stopped. Anyway, to some extent there is a change. But unless you make alternative arrangements for loans to the agriculturists and poor peasants, they would be forced to rely on and go to money-lenders. I found out from my own experience that in Malda, West Dinajpur, Howrah and the 24 Parganas, the peasants would not even divulge it publicly lest the money-lender should come to know and victimise them when it comes to getting loans from the money-lender because there are no alternative arrangements for taking loans. Now, such things are happening.

Sir, all our Party comrades, most of our Party leaders, MPs and MLAs, under the instruction of the Party, have been sent out to the villages. We have all gone to Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Assam and all over the country and we are still going. We are gathering information. And I say with a sense of responsibility, and we have brought it to the notice of the authorities here as well as at the State level that things are not what they are made to look from the newspaper advertisements and statements of Ministers. I don't think there is any item in the 20-point Programme which said that the Ministers must make false statements. If that is so, that has been magnificently implemented. But I do not know whether there is any written or unwritten item in the 20-point Programme that the officials should tell untruth, make false claims and create an impression in the country as if the 20-point Programme is going on like a jet plane. It is not so, Sir. Why? Number one: The vested interests are coming in the way of the implementation of the 20-point Programme. Some of them seem to have taken a liking for the 4-point programme. I think, the 20-point Programme should be implemented. After that, I have no objection to the 4-point programme being implemented. But the 4-point programme should not be taken as a cover for diverting attention from the 20-point Programme. I should like to know which programme we have to implement today, the 4-point programme or 20-point Programme or 24 points? Kindly tell us very frankly. Now, nothing is being said. Sir, I am saying this thing because we have stood together—they and we—in the fight against the reactionary elements and for the implementation of the 20-point Programme. Let it be clear. What has happened to the urban property ceiling, or whatever it is, about that vacant land? We hear and read about the statements in the newspapers.

[Shri Bhupesh Gupta]

Government takes so much time even to formulate the policy but they do not take time to demolish houses in Delhi and do whatever they like to force people to come to their scheme of sterilisation and so on. When it comes to the question of the implementation of the urban property ceiling or whatever it is, there is a discussion, there is a debate, there is prevarication and when it comes to sterilisation—forcible in some cases—well, Sir, things move very quickly. These things have been brought to notice. It is no use hiding what happened in the Turkman Gate. The history will be told and retold, if not today, tomorrow or the day after. All along, we shall not be living under the clouds and darkness of emergency. We know it very well.

Sir, we are all for family planning. Well, we need not be lectured about to persuade, educate and enlighten and see that it is done. We want it; it is absolutely necessary in a country like ours. The Government have taken a stand. I entirely endorse Shrimati Indira Gandhi's stand that family planning should not be carried on by methods of coercion. But, do our Officials listen to her? Or, does she take adequate steps to see that what she says is being heeded, or is there any communication gap between what is being done at the grass-root level and where she sits in authority and power? I should like to know it. If the communication gap is there, well, stop it, make the situation better because I cannot believe that a person like Shrimati Indira Gandhi, for whose commonsense I have great respect, would be in favour of forced sterilisation. I do not believe it, because I know her for many many years. But, still, such things happen and incidents take place, like firings, shootings, lathi-charges and all these kinds of things. These are not a part of the 20-point programme. If that is so, declare it that it is a part of the 20-point programme. The 20-point programme is an excellent programme to be implemented in a spirit of democracy, love for the people, patriotism of the highest order, always by enlightening, educating, inspiring the masses to join in the activity of nation building. You do not require bulldozers to implement this 20-point programme.

Sir, you may think that our voices will be silent. They will not be silent. I would ask the Lt. Governor of Delhi to respect the spirit of the 20-point programme and the situation that brought it about. Do not take undue advantage of the situation because *Samachar* is under the control, because press is under the control, because what we say here, many of the things we cannot do. Sir, that is not serving democracy, let alone taking the country forward.

Now, coming to another aspect of the 20-point programme which concerns this Resolution also, what has happened to the monopoly capital? They never had it so good. Everyday I get up, I come across a statement by the Birlas that they are also happy today. We are told Mr. G. D. Birla is in the United States of America meeting the leaders of Zionism in order to mollify the feelings of the Zionist community in the United States of America because money comes from there, as given out in the Congressional Committees and so on. Find it out. The day before yesterday, Mr. G. D. Birla made a statement, how happy he was, how fine the country was going. And yet, in the newspapers, we see income-tax cases, wealth-tax fraud cases and other things have been opened against him. I should like to know, how many cases of income-tax evasion one would require to become such a prominent, adored and admired industrialist of the country as Mr. G. D. Birla or Mr. K. K. Birla?

3 P.M. These are very straight questions that I put before you. Monopoly capital cannot be strengthened in this country. Monopoly capital is responsible for the advent of the right reactionary forces and the fascist forces, whether in our country or in other countries. Historical experience of our contemporary times is that monopoly capital feeds fascism. Yet it is the monopoly capital which is having a field day in our country, carrying on

depredations against the working people, denying them their rights and carrying on closures, lay-offs and all that as if there is no law for them. Never have we experienced such a situation. I have not experienced such a situation, ever since I came to Parliament some 25 years ago, when monopoly capital was so happy. Even in those days when we had the Second Five-Year Plan and gave prominence to the public sector, G. D. Birla and other people did not speak in the accents of happiness and joy in which they are speaking today. This should make us sit up. That is why I say that monopoly capital should not be strengthened. Is it going to increase industrial production? If our industrial production has gone up—we are very happy about it—it is because of our public sector and the Prime Minister is right in paying tributes to the working people of our country. Why should the Birlas, the Tatas, the Singhanias, the Bajorias and others take advantage of it in these matters? Monopoly capital should not be a shield for covering up the rotton elements in our society whose hands are full with economic and social crimes, who have to answer generations after generations for the economic malpractices, corruption, plunder, loot and all the rest of it, which they have committed because of certain policies of the Government. May I ask Mr. T. A. Pai and Mr. Subramaniam to kindly imbibe the spirit of the twenty-point programme, find their way not to surrender so shamelessly to monopoly capital? Sir, monopoly capital is a threat to democracy and independence and is a stalking horse for imperialism and neo-colonialism. There is another scandal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Mr. Bhupesh Gupta, you are the senior-most Member. I need not have to remind you. Please conclude.

SHRI BHUPESH GUPTA : You need not take the trouble of reminding me the obvious. I am very glad that you have reminded me of my old age. But please do not do so in the case of women also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : I am reminding you of four seniority and not your old age. You are stil young.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am very glad. But seniority is now at a discount. Take the case of benami land transfers. They say that all such transfers would be legalised. which part of the twenty-point programme says that such land transfers should be legalised? Now, all these land transfers, land transfers to the wife, to somebody else's wife—if you know how to carry on affairs—and so on, would be legalised. Land transfers to the relatives, to the friends, to the cows, to the buffaloes, to the elephants and so on would be legalised because you can always find some people appearing in that name. Everybody knows. In Andhra Pradesh and other places, cows do have names and lands are transferred to the cows. Now, all these land transfers would be legalised. Does it mean implementation of the land reforms? Sir, previously there was a voluntary disclosure scheme whereby we allowed the black money to become white and gave them tax exemptions. They declared about Rs. 2,000 crores' worth of black money and we got Rs. 200 crores in taxes from them. Their money became white, as white as the khadar worn by our Congress friends. But now, benami land will also be made white and legal. You can imagine what sort of a thing it is going to be. Where is it in the programme? Was there any conference called by the Prime Minister or the Congress Party or those who discussed the matter? Was there any national consensus taken? Nothing of the kind! Some people somewhere had contrived that benami land should now be made legal and so it will be made legal. A Bill will be brought in the other House. So what is the use of our talking about these things?

Finally, I would like to say one thing. I do not have the heart to talk because, I tell you, parliamentary institutions are not being respected by some people. I am not saying "You". Many of you respect them,

[Shri Bhupesh Gupta]

share our sympathies and feelings. We have worked together and we shall work together, but there are people—officers and others—who have taken it into their head that Parliament is an expensive talking shop and they would be doing whatever they like. I strike a note of warning : We have reached a point when the 20-point programme has become a challenge and we will be judged by how it is implemented, for which local people's committees at the grass-roots level including all kinds of people who are interested in it are very very essential. I do believe, Sir, that many Congressmen at our level are as genuine as I am for the implementation of the 20-point programme. Sir, many of them are interested in weakening the position of monopoly capital and the exploiting classes and it will be my endeavour to work with them. And it should be their endeavour to work with us.

Therefore, Sir, I suggest that this resolution be taken in such a manner that it inspires better rapport between all of us in order to come to an understanding not only for issuing all these statements but also for involving the masses for the implementation of the 20-point programme and also, at the same time, to be vigilant against those who are giving concessions to the monopolists that are trying to exploit the emergency situation in order to regroup the forces of right reaction again in order that the progressive forces can be hindered in their advancement.

Sir, the mover of the resolution wants the right to private property removed and I fully support him. But you will not succeed.

(*Interruptions*)

My friend there has got up. I hope you will fully support me in this matter. We stand together for the implementation of the programme.

This resolution merits the support of the entire House. Once again I am beholden to my friend who has brought this resolution. It is the echo of the voice of sanity, reason and progress with which we cannot but join with equal sincerity and equal hope.

Thank you.

श्री जगदीश जोशी (मध्य प्रदेश) : सभापति जी, माननीय सदस्य भूपेश जी ने काफी विस्तार में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और दरअसल उनके विशद समर्थन के बाद कोई खास मुद्दा रह नहीं जाता उन्होंने इस प्रस्ताव की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की है और बहुत-सी समस्याओं पर, भले ही उनको थोड़ा अतिरंजित किया हो, प्रकाश डालने की कोशिश की है। कुछ असुविधाएं, कुछ असमानताएं, कुछ गडबड़ियां एक बड़ी व्यवस्था में हो सकती हैं। जितनी रफ्तार वह समझ रहे हैं उतनी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी तेजी से वह चाहते है, उतनी तेजी नहीं हो पा रही है। उन्हीं की तरह हम में से भी बहुत से लोग तेजी चाहते है। लेकिन इस देश की प्रक्रिया, देश की व्यवस्था, इस देश के ढर्रे को देखते हुए जो गति चल रही है उसमें जितनी अधिक गति हम लोग ला सके ताकि उससे सारे देश में एक नई एकात्मकता बनी हुई है। इस प्रस्ताव का मूल रूप दो खंडों में है। पहले खंड में प्रस्ताव में कहा गया है कि आर्थिक नीति का निरूपण इस प्रकार किया जाए जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमता समाप्त हो। यह इस प्रस्ताव की अन्तरात्मा है। मैं चाहता था कि भूपेश गुप्त साहब इसके उत्तरार्द्ध में कुछ कहते। उन्होंने उसके सामयिक रूप पर कुछ कह कर अपना प्रवचन समाप्त कर दिया।

सामाजिक और आर्थिक गति का जहां प्रश्न उठता है वहां यह सही है कि कार्यक्रम को कुछ सगुण बनाना पड़ता है। अभी तक हमारी पंचसाला योजनाएं जिन उद्देश्यों की ओर चल रही थी उनको एक त्वरित गति और एक लक्ष्य देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को सोपान तैयार किया। 20 सूत्री कार्यक्रम की सीढ़ियां बनीं और उन सीढ़ियों के जरिए हम एक मंजिल तक पहुँच सकते है। अलग-अलग सगुण स्वरूप हो गए

हैं। इनसे मालूम पड़ता है कि आखिर हम अमली-तौर पर थोड़े समय के अन्दर कई चीजें कर सकेंगे। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं। आर्थिक समानता के विषय में जो कदम उठाए गए हैं, उनमें बुनियादी लोगो को जमीन देने का मामला, फालतू जमीन का मामला या सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिये बन्धक मुक्ति का मामला, दास प्रथा उन्मूलन का मामला है। इन सारे विषयों को नए सिरे से एक गति दे कर जिस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है वह दिशा हम को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रस्तावक महोदय ने इससे आगे एक कदम बढ़ाने की चेष्टा की है। जरूरी है कि जहां हम अल्पकालीन कार्यक्रम को लागू करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं वहां हमें एक दीर्घकालीन कार्यक्रम की तरफ भी दृष्टि रखनी चाहिये। अगर हमारा दीर्घकालीन कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक समता को स्थापित करना है तो हमें अपने लक्ष्यों को सगुण बनाना पड़ेगा और उन लक्ष्यों को सगुण बनाने के लिये कुछ उद्देश्यों को साफ-साफ रखना पड़ेगा। आर्थिक समानता के विषय में अगर हम मोटे तौर पर एक सिद्धान्त स्वीकार कर लें कि न्यूनतम आमदनी और अधिकतम आमदनी के बीच में क्या अनुपात होगा और उस अनुपात का निरूपण कर दें और वह अनुपात अमली तौर पर स्वीकार हो जाए—संसद् और इस देश की सरकार उसको स्वीकार कर ले—तो असमानता दूर हो सकती है। वैसे असमानता पूर्णतः दूर होना असम्भव है। मैं उन लोगों में नही हूं जो असामान्य बात कहूं। कार्ल मार्क्स भी इसको प्रतिपादित नही कर सके। उन्होंने कुछ मर्यादाएं बांधी हैं, जहां आर्थिक नीति का निरूपण होता है। जहां आर्थिक नीतियो का निरूपण हो वहां हमें भी अपनी कुछ मर्यादाओ का खूंटा सामान्य रचना के लिए बांधना चाहिये, जो कुछ समय के लिये चले। इन उद्देश्यो के आधार पर हमारे कार्यक्रम सफल हो सकेंगे।

मेरा निवेदन यह है कि न्यूनतम आमदनी और अधिकतम आमदनी के बीच क्या अनुपात हो, यह हमें देखना है। हम देखते हैं आज आमदनी में बड़ा भारी अनुपात है। एक तरफ 8 आने, 9 आने रोज एक व्यक्ति को मिलते हैं और दूसरी तरफ हजारो रुपये की आमदनी रोज की एक व्यक्ति की है। जहा इस प्रकार की विषमता हो वहां आप आमदनी में बराबरी अनुपात नही ला सकते। लेकिन कम से कम उसके लिये प्राथमिक तौर पर खर्चों पर रोक जरूर लगा सकते है।

खर्चों पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने काफी कदम उठाए है। सरकार ने पैट्रोल पर टेक्स लगाया, ताकि जो बड़े-बड़े लोग इसको इस्तेमाल करते है, उनके खर्च पर कुछ रोक लगे। आप जानते है कि पैट्रोल का ज्यादातर उपयोग सरकारी विभागों, बड़े-बड़े मेनोपोली हाऊसेज और जिनके पास फालतू रुपया होता है, उनके द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार ने कासपीकुअस कंजम्पशन और व्यक्तिगत भोग पर अनेक प्रकार की रोक लगाई है। आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि जो भोग की वस्तुएं है, जिनका उपयोग अमीरो द्वारा किया जाता है उन वस्तुओ पर रोक लगाई जाए। जो अमीर लोग है, उनके खर्च पर अंकुश लगाया जाए।

हमारे देश में एक तरफ तो म्युनिसिपल कमेटी के स्कूल चलते है और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल चलते हैं। मैं आपके माध्यम से पंजाब सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वहां की सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब राज्य में सारे पब्लिक स्कूल खत्म कर दिये जाएंगे। मैं समझता हूं कि सबसे बुनियादी और इन्क्लाबी काम पंजाब की सरकार और वहा के मुख्य मंत्री ने किया है। वे हम सब लोगों की प्रशंसा के पात्र है; क्योंकि असमानता की बुनियाद इन्ही पब्लिक स्कूलों से शुरू होती है। हमारे देश में आजकल स्थिति यह है कि अमीर का बेटा तो 600 रु० या 700 रु० माहवार खर्च होने वाले पब्लिक स्कूलों में पढ़ता है और एक गरीब का बेटा म्युनिसिपल कमेटी के टाट-पट्टी के स्कूलों में पढ़ता है। आखिर इस प्रकार की हालत में विषमता कैसे दूर होगी? एक तरफ तो म्युनिसिपल कमेटी के स्कूलों में और गांव के स्कूलो में टाट-पट्टी भी बच्चों को बैठने के लिए नही मिलती है, दूसरी

[श्री जगदीश जोशी]

तरफ पब्लिक स्कूलों में पांच सौ या छः सौ रुपए माहवार खर्च किये जाते है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शैक्षणिक असमानता ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की असामनता विद्रोह की भावना पैदा करती है। सरकार ने सेन्ट्रल स्कूलों के रूप में कुछ स्कूल खोल कर पब्लिक स्कूलों की वृद्धि को रोकने का प्रयास किया है। आज हमारे देश के अन्दर स्थिति यह है कि जो आदमी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते है वे अभिजात्य नहीं माने जाते है। टाट-पट्टी पर बैठने वाला लड़का आई०ए०एस० और आई०एफ०एस० की परीक्षाओं में नहीं बैठ सकता है। अगर वह परीक्षाओं में बैठता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पाता है। यही नहीं इस प्रकार के बच्चे बड़े-बड़े कारखानों में नौकरी नहीं पा सकते हैं, एन०डी०ए० में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक एक ऐसा कानून न बना दिया जाए कि जो कांवेन्ट स्कूलों के लड़के होंगे या पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए लड़के होंगे, उनके 10 परसेन्ट नम्बर कम माने जाएंगे, तब तक जो म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़े हुए या गांवों के प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हुए लड़के होंगे उनको उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक आप पब्लिक स्कूलों के लड़कों के 10 परसेन्ट नम्बर कम नहीं करेंगे, तब तक टाट-पट्टी पर बैठ कर पढ़ने वाले लड़के उनका मुकाबला नहीं कर सकते है। हमारे देश में जो असामनता की बुनियादी जड़ है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। इसी प्रकार से हमारे देश में जो जाति प्रथा का कोढ़ रहा है, उसके कारण भी कुछ जातियां अपने आपको ऊंचा मानती रही और दूसरों को नीचा मान कर उनका शोषण करती रही। आज भी हमारे देश में इस प्रकार की कुछ जातियां है जो कुछ काम नहीं करती है। इस देश के इतिहास को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस देश में पिछले चार-पांच सौ वर्षों से यह प्रथा चल रही है कि राजा लोग थोड़ी-बहुत मात्रा में बदलते रहते हैं, लेकिन जो दूसरे नम्बर के राजा है, वे लगभग वही चलते आ रहे है। मुल्क के अन्दर नम्बर 1 के राजा तो बदलते रहे, लेकिन नम्बर 2 के राजा पिछले आठ सौ वर्षों से वही चले आ रहे है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत (राजस्थान): ये नम्बर 2 के राजा कौन है, यह तो बता दीजिये।

श्री जगदीश जोशी: नम्बर 1 के राजा वे रहे है, जो राजा कहलाते है और राजगद्दी पर बैठते है। नम्बर 2 के राजा वे है जो राज्य का काम करते है, जैसे दीवान और बड़े-बड़े अधिकारी लोग। आप तो रानी है, इन बातों को अच्छी तरह से समझती होंगी।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश के अन्दर जो दबे हुए लोग है, जिनका शोषण किया गया है, जो हाथ से काम करने वाले लोग है, जैसे हरिजन, आदिवासी आदि, उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि शासन में और शासन के कार्यक्रमों में और अन्य सारी सुविधाओं में उनका जो अनुपात रखा गया है, उसको बढ़ा दिया जाए।

वैसे हरिजनों और आदिवासियों के लिए आपने अनुपात रखा है, सविधान में इसकी व्यवस्था की है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बाकी लोगों को भी शामिल करके--आबादी भले ही उनकी अधिक हो--जिसमें देश की सारी महिलाएं, अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग, द्विज वर्ग के लोगों को छोड़ कर और बाकी जो है, उनको 100 में से 60 स्थान दीजिये, दस साल, बीस साल के लिये दीजिये, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा के लिए कर दीजिये, एक प्रकार से इन्वाल्वमेंट ... (*Time bell rings*) मैं खत्म कर रहा हूं, तो एक इन्वाल्वमेंट लोगों में आ जाएगा और उस इन्वाल्वमेंट के बाद इस देश में गति आ जाएगी, इस देश में ना-बराबरी, सामाजिक विषम , जो आज तक रही है, वह सामाजिक विषमता समाप्त हो जाएगी।

अब मैं सम्पत्ति का अधिकार और राइट ऑफ इम्प्लायमेंट की बाबत दो मिनट में कह कर समाप्त करता हूं। सम्पत्ति के अधिकार की बाबत कहा गया है कि इसे खत्म कर दिया जाए। पूरा खत्म करने में कई खतरे है, मैं उनसे आपको आगाह कर दूं। पूरा खत्म कर दिया जाएगा तो आज जो देश की व्यवस्था है, इसमें 2 एकड़ वाले की जमीन चली जाएगी; क्योंकि 2 एकड़ वाला घूस नहीं दे सकेगा इन्जीनियर को, उसी की जमीन से सड़क जाएगी और 50 एकड़ के ऊपर से सड़क नहीं जाएगी; क्योंकि वह घूस दे देगा। तो 2 एकड़ वाले की तो जमीन चली जाएगी, एक छोटा-मोटा परचून वाला है, उसकी दुकान लूट ली जाएगी, लेकिन मोनोपोली वाले की दुकान के लिए कोई बोलेगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सम्पत्ति का अधिकार आप सीमित रखें। आपने कभी मानदण्ड लगाया है कि सरकार के कदम उस दिशा की तरफ जा रहे हैं? मेरा निवेदन यह है कि सम्पत्ति को परिभाषित कर दीजिये। अवैध ढंग से कमायी सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं होगी, देशद्रोह के साथ कमायी सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं होगी, शोषण के द्वारा कमायी गई सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं होगी, इस प्रकार कुछ केटेगरीज ऑफ प्रापर्टी को आप सम्पत्ति की परिभाषा से अलग कर दीजिये और बाकी सम्पत्ति को लेने का निर्णय लीजिये, तो आदमी जो मेहनत करेगा, मेहनत की जो रोटी खाएगा, वह हमारा भाई बन कर इस देश में रह सकेगा और बाकी जो हराम की कमायी खाता चला जा रहा है वह इस देश की सम्पत्ति का अधिकारी नहीं रहेगा लेकिन मशक्कत और पसीने की कमायी जो कर रहा है उसको न्यूनतम सम्पत्ति रखने का अधिकार आपको देना होगा। यह गारण्टी आपको देनी होगी। लेकिन अगर आप इसको परिभाषित कर देंगे तो अच्छा होगा।

अब रह गया नौकरियों का, इम्प्लायमेंट का सवाल। यह बड़ा मूल प्रश्न है और आवश्यक प्रश्न भी है। इस देश में बड़ी भयंकर बेरोजगारी है। मैं इस पर आने के पहले एक शब्द कह देना चाहता हूं, बहुत अच्छा है कह दूं, क्या सरकार इस स्थिति में होगी आज कि उस अधिकार को देकर उसे पूरी तरह से ईमानदारी से लागू कर सकेगी। मैं समझता हूं, सरकार कहेगी हम उसको लागू करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप आर्थिक दिशाओं पर कामयाब हो जाते है, सामाजिक दिशाओं पर कामयाब हो जाते है, सम्पत्ति के प्रवाह को, केन्द्रीकरण को रोक सकते है, भोग की व्यवस्था पर चोट कर सकते हैं, उसको छीन सकते है उनसे, तब एक नयी आशा जागेगी और उस नयी आशा के साथ आप करोड़ों लोगों को, मेहनतकश लोगों को, काम दे सकेंगे और देश एक नयी गति के साथ आगे बढ़ सकेगा।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will strictly confine myself to the scope of the Resolution. I do not have that much wind in my lungs, like my esteemed friend, Mr. Bhupesh Gupta, to shout and express my points strongly, nor do I have the musical voice of my friend, Mr. Jagdish Joshi...

SHRI BHUPESH GUPTA: What do you mean by musical voice? He should be asked to join the Sangeet Natak Akademi then.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am in favour of the Resolution in the sense that this is an ideal stage which we want to reach. But on the question of adopting this at the moment, I certainly have my reservations. The Resolution says:

> "...the economic policies should be so regulated as to remove social and economic inequalities and create maximum employment opportunities in the country and in order to achieve these objectives, urges upon the Government to take immediate steps to amend the Fundamental Rights enshrined in the Constitution of India by deleting therefrom 'Right to Property' and including therein 'Right to Employment'."

As you all know, after five years of darkness and disturbances we are now entering into a new phase and trying to build up a new India. After the emergency a sense of discipline has come in the country. It

[Shri Brahmananda Panda]

is seen in every sphere of activity. But this discipline has not become yet a part of our life. So, the experiment is still going on. As my friend pointed out, the Twenty-Point Programme is a bold step taken in the right direction to achieve what is stated in this Resolution.

SHRI BHUPESH GUPTA : The step should not be like that of Johnny Walker.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : We do not want to run like a horse.

SHRI BHUPESH GUPTA : I do not want you to run like a horse. But you should not be like Johnny Walker.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : We believe in prohibition.

The picture painted by Shri Bhupesh Gupta is not as gloomy as he thinks. After all when something good is taken up, there is bound to be some abuse. In the Twenty-Point Programme, especially in the field of land reforms, I think right from the Prime Minister down to the low level Congressmen, we are doing something for the down-trodden. We are all interested in it and we are eager to get something out of it. In every State something is being done and he might know what is being done in his own State. In every State Central Committees have been formed. At district level, committees have been formed. This has been done in Orissa. We are going to block level very soon. The difficulty is, as they say, habits die very hard. When you want to change the country, whether it is India or any other country, we should not forget the historical conditions and the cultural content of the nation. What are the historical conditions in India ? We had five years of strikes, five years of disturbances, five years of chaos and five years of clamour mongering which have not only debilitated our economy but have demoralised many of our political leaders. From such a stage if we want to take the country forward, we need some time. That time cannot be time-bound. We have to proceed from one experiment to another. Maybe from Twenty-Point Programme we may have to go to 24-Point or 48-Point programme. As we proceed, we commit mistakes and from our mistakes we learn. When you are thinking of a new India and a new society, we have a right to commit mistakes. Nobody can be perfect. When you experiment with people, many difficulties arise. I do not agree with my friend that *benami* land is going to be white land. But I do agree that *benami* land should not be taken as white land. Have not these voluntary disclosures given us some profit ? There are some people who are afraid to disclose. So the good gesture shown by the Government has yielded results and many people came forward with their disclosures and I am sure many more will come forward and disclose what they have. In a country like India with its vastness, with so many diversities and classes which are all inter-twined, it is not very easy or simple to cut out this or that. I would rather assure my friend Bhupesh Babu that the way in which the country is moving today is in the right direction. What we need are patience, labour, time, devotion to duty, discipline . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : And courage.

AN HON. MEMBER : Right to work or right to commit mistake which do you prefer ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : They are inter-wined. You cannot separate the one from the other. When you dig a well and you do not get water there, you cannot say that your effort was a waste. You have to dig a well elsewhere to get water and you cannot say that your efforts were wasted. So, when you make an experiment, there will be difficulties and you have to tide over those difficulties. I think we are doing something now for the poor people of this country which they have been expecting for decades.

Then, as for the last portion of this Resolution, my friend wants that the right to property should be taken away from

the Fundamental Rights in the Constitution and he wants the right to employment to be included therein. Sir, so far as taking away the right to property is concerned, I have no objection to it and it will be done. But, so far as the other thing is concerned, that is, the right to employment, I think we can only make lusty speeches. But, Sir, are we in a position to grant it at this stage of development of our economy ? It is just not possible. How can we do it ? And, the right to what type of employment ? When we say that there should be a right to employment, I would rather say that there should be a right to duty also.

SHRI BHUPESH GUPTA : You should appreciate the sentiments behind this Resolution.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : This is a programme and it is not a question of any sentiment or emotion. I am a realist and I am speaking about the realities.

SHRI BHUPESH GUPTA : But only then you can do something and come to the society and declare : "Yes, there will be the right to employment". You must know that even today we have not about 49 lakhs of people who are educated and who are unemployed in the country; the number of the educated unemployed in the country is 49 lakhs and it has appeared in today's papers also.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am coming to that. Educational system also has to be reformed. We simply clamour for degrees and enter the colleges and we come out with B.A. and M.A. degrees. But everybody wants a Government job only. Now, which Government under the sun can employ everybody? Is it possible at all? If a doctor is transferred from an urban area to a village, he is not prepared to go; if a teacher is transferred to a place just ten miles away from Delhi, he is not prepared to go: and if a Tehsildar is transferred from one taluk to another, he is not prepared to go. So, there should be a fundamental change in our attitude and that must come about soon.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : Even the Members of Parliament are not willing to go out of Delhi once they come here.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Yes, it is so. These are the difficulties. Now, we are doing things one by one and we are proceeding step by step. We know what we have done, whether we have committed any mistake and what our next step will be. Every step of ours is a measured step and is taken with caution. It is not possible to build up a society of a different nature all of a sudden and the society must come by evolution and that evolutionary process must be guided and we are guiding that evolutionary process. Therefore, I am not feeling that much pessimistic thinking that we would be losing things or that India is moving in a direction in which we do not want it to move and so on. We know our goals ; we know our objectives; and we know the steps to be taken. Every step that we take is a firm one and we also know that that step is a definite one. So, I hope that my friend, Shri Bhupesh Gupta, would agree with me that, whatever may be his thinking or whatever may be the ideals he may be having in his mind, we are also trying to reach towards that goal.

SHRI BHUPESH GUPTA : I said that you could move in a much faster and a better way. That is what I said in my speech.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Pardon?

SHRI BHUPESH GUPTA : The burden of my speech was that we could move in a much faster and better way.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : But it depends on many things. It depends upon the momentum and the road on which you take your car. All these things are there. So, my point is this: So far as the right to employment is concerned, we are not in a position to grant it at this stage and if we have to change the Fundamental Rights in our Constitution, we have also to define what our duties are and what our responsibilities are and not merely our

[Shri Brahmananda Panda]

rights. All these years we have been harping on our rights only and that is why we have been having many demonstrations and strikes and lock-outs and lay-offs and so on.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Are you agreeable to the abolition of the right to idleness also?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: But that can be enshrined in the Constitution. For that, I think, we have to search our own hearts; that is all. Now, Sir, even for changing the Constitution, the Congress Party has set up a Committee and there will be a national dialogue and we must see now as to how the Constitution as a code of discipline can adjust itself to the changes that we are going to make and the changes so far made and to the historical conditions that prevail in the country.

Finally, Sir, before you ring the bell, I would like to say that this is a very good Resolution and I am in favour of it because, in spirit, it shows us the way to the stage that we want to reach. But, at this juncture, the adoption of this Resolution will not only slacken our progress, but also it will create such difficulties that it would be very difficult for us to surmount them. Thank you, Sir.

श्री ओ३म्प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नत्थी सिंह जी के प्रस्ताव को मैंने ध्यान से पढा है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनसे मैं सहमत हूं और कुछ ऐसी हैं कि जिन से मैं सहमत नही हूं। इसलिये जिन बातों से मैं सहमत नहीं हूं वह बातें ऐसी है कि जो जनता और देश के हित में नही है और इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नही करता, विरोध करता हूं। जिन बातों का मैं समर्थन करूंगा वह भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो या नहो, यह अच्छा है या बुरा है, इसकी कसौटी मेरे और आपके विचार नही है, अपितु इसकी कसौटी जो है यह है कि कौन सी बात देश के हित के लिये अच्छी है और कौन सी बात देश के हित के लिये बुरी है। देश का हित ही जनता का हित है। अगर यह प्रस्ताव देश हित मे हो तो स्वीकार किया जाय और इसका समर्थन होना चाहिए और अगर यह देश हित में नहीं है तो यह स्वीकृत नही होना चाहिए। जनता का हित किस बात में है, देश का हित किस बात में है ? देश का हित एक ही बात में है कि देश मे रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिले। देश का उत्पादन अधिक से अधिक हो, ताकि किसी को कोई अभाव, कोई कठिनाई न रहे, गरीबी देश में न रहे और सब लोग आराम के साथ रह सकें। इसके मार्ग संसार में दो हैं। आज दो प्रकार के उपाय इसके लिये चल रहे हैं। एक प्रजातंत्र के आधार पर चल रहा है और दूसरा साम्यवाद के आधार पर चल रहा है, लेकिन यह प्रस्ताव न हियों में है और न शियों में। यह न इधर में है और न उधर में। साम्यवादी मार्ग, जिसमें देश की तमाम प्रापर्टी की मालिक गवर्नमेंट होती है और सब लोगो को काम करने का अधिकार रहता है। रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है। सभी सुविधाओं का उत्तरदायित्व सरकार ले लेती है। यह एक मार्ग है जो रूस मे है, चीन में है। वह स्वीकार करने की बात हो तो स्पष्ट सामने आनी चाहिए। एक ही शब्द मे कहना चाहिए कि साम्यवादी मार्ग पर चल कर हमको इन तमाम समस्याओं का समाधान करना है।

श्री नृपति रंजन चौधरी : (आसाम) हम लोग साम्यवादी नही है, लेकिन हम लोगों ने साफ साफ कह दिया है, जनता को कि हम साम्यवाद की राह पर चलेंगे।

श्री ओ३म्प्रकाश त्यागी : आप कांग्रेस (आर) में हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने यह कभी नही कहा।

श्री नृपति रंजन चौधरी : प्रधान मंत्री जी ने कहा है। कहा है।

श्री ओ३म्प्रकाश त्यागी : उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा।

श्री नृपति रंजन चौधरी : उन्होंने कहा है। I am not interrupting. This is just a clarification. नयी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्लियरकट हम लोगों ने कह दिया था कि समाजवाद की राह पर हम चलेंगे।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : सुनने की चेष्टा करो, मेरे दोस्त। साम्यवाद और समाजवाद मे बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा है कि हमारी पालिसीज़ समाजवादी है, साम्यवादी नहीं। यह बात स्पष्ट रूप में समझ लीजिए आप। एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने कहा है कि उनकी नीति समाजवादी है, सोशलिस्टिक है, कम्युनिस्टिक नहीं हैं।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : समाजवादी मायने क्या, त्यागी जी ?

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : अगर आप मेरे पास आ जायं तो मैं समझा दूंगा। लेकिन आप तो सोशलिस्ट रहे है, अगर आप को ही उस का ज्ञान न हो तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं। जो सोया हुआ है उस को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना करता है उस को क्या जगाया जायेगा। आप फिर सुन लें...

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : आप का टाइम खत्म होता जा रहा है।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैं कह रहा हूं मै जो बात पेश कर रहा हूं, किसी कारणवश या स्वार्थवश बात नहीं कर रहा हू। मैं एक विचार रख रहा हूं, उस पर आप विचार कीजिए जवाब देना हो तो जवाब दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक हैं। मै आपको उदाहरण देता हू। आज हमारे देश में गरीबी भी है, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। देश में ऐसे आदमी हैं जिनको रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, मैं दिल्ली में एक घंटे में उनका प्रबन्ध कराये देता हूं। 1 हजार, 5 सौ या 400 आदमी ऐसे हों, उनका इलाज मैं बता देता हूं। मैं उनकी टोली बनाऊंगा और सरकार के खिलाफ नारे लगाऊंगा। उनको मिनटों में पुलिस वस में भरकर शानदार लाखों रुपये का मकान बना है तिहाड़ में ले जायेगी, रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, बढ़िया कपडा मिलेगा, ठीक टाइम पर रोटी और खाना मिलेगा। और क्या चाहिए आपको ? वही मैं कह रहा हूं। इसके माने है कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी कुछ चाहिए। वह आवश्यक वस्तु है स्वतंत्रता, फ्रीडम आफ ऐक्शन। रशिया में, चाइना में यह नहीं है। मैं इंदिरा गांधी को धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि वह समझती है इस बात को और वह कहती हैं कि वे समाजवादी हैं। लेकिन आप जैसे उनके अनुयायी कहां ले जाएगें नेता को ?

कुछ मनोनीत सदस्य : आप आ जाइये।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : इसलिए मै कहता हूं ... (*Interruption*)

उप-सभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : आप लोग शान्त रहिए। टाइम के भीतर उनको खत्म करना है।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : दूसरा रास्ता है प्रजातंत्र का। प्रजातांत्रिक मार्ग में बहुमत के विचार से, फ्रीडम आफ थाट, विचार की स्वतंत्रता के साथ में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की जाती है। प्रस्ताव में आपने कहा है कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त किया जाए। मैं यह कहता हूं कि सम्पत्ति का अधिकार सबको दिया जाए। अगर प्रजातांत्रिक आधार पर देश को खड़ा होना है तो प्रजातांत्रिक मार्ग ही अपनाना पड़ेगा।

अधिक उत्पादन करने के लिए, देश में अधिक सस्ते दामों पर चीजे मिलें, इसके लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक तो उत्पादन केन्द्रो के साथ उनमें काम करने वालों का संबंध। मेरा शब्द उसमें होना चाहिए। मेरा खेत, मेरा कारखाना, मेरा घर। मेरा जहां शब्द लगेगा, आदमी पूरी शक्ति के साथ उसमें काम करेगा। दूसरे जो उत्पादित माल है उसका बाजार में कंपिटिशन होना चाहिए। कंपिटिटिव प्राइस सामने आनी चाहिए ताकि दाम सस्ता हो। मोनोपली होगी तो कोई भी चीज सस्ती नहीं मिल सकती चाहे मोनोपली सरकार की क्यो न हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति का अधिकार सबको न हो, बल्कि जो खेत जोतता है खेत उसका हो। जो काम जहां करता है, कारखाने में है, मिल में है तो उसका मालिक वह हो। जिस फैक्टरी में काम करने वाला जो मजदूर हो, उसको मलिकाना अधिकार मिलना चाहिए। अगर वह मालिक बनकर खड़ा हो गया जिसने पूंजी लगाई है तो वह ठीक नहीं। मैं समझता हूं कि मालिक जो काम करता है उसको होना चाहिए ताकि उसके नफे और घाटे का सम्बन्ध उसके साथ जोड़ा जा सके। अभी पांडा जी रो रहे थे कि हड़ताल होती हैं। आज के बाद आप मजदूरों को फैक्टिरियों में मालिक बनने दीजिए। उनको लाभ हानि से संबन्धित कीजिए तो देश में हड़तालें

[श्री ओ३म प्रकाश त्यागी]

बन्द हो जायेंगी, डिमांस्ट्रेशन बन्द हो जायेंगें, नारे लगाये जायेंगे कि काम के घंटे बढ़ाओ । कंपिटिशन में काम होगा । हमारी फैक्टरी में ज्यादा आमदनी होगी तो हमें अच्छा घर मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, यह भावना मजदूरों में होगी । फैक्टरी में प्रतिस्पर्धा होगी । मोनोपली नहीं होगी । मोनोपली खतरनाक होती है । इसिलए मैं कहना चाहता हूं कि आप मालिकाना अधिकार देने की चेष्टा कीजिए ताकि यहां उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके ।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि सरकार को एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे कोई सम्पत्ति को एक्सप्लाएट न कर सके । सम्पत्ति जिसके पास है उस सम्पत्ति पर आपको एक सीमा बांधनी चाहिए । यह कहना चाहिये कि यहां तक सम्पत्ति होनी चाहिये और अगर कोई इससे ज्यादा सम्पत्ति रखेगा तो उस पर सुपर टेक्स लगेगा । अपने आप सरकार के पास सम्पत्ति चली आएगी । साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आदमी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश न की जाए । अगर आपने राईट आफ प्रोपर्टी खत्म कर दी तो जो योग्यता है वह कुंठित हो जाएगी, आदमी में जो योग्यता, क्षमता है वह खत्म हो जाएगी । यह मेरी मान्यता है ।

आपने आर्थिक समानता की बात भी कही है । इस संसार में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह है विषमता ।

एक माननीय सदस्य: कोई खुदा बनता है तो कोई बंदा ।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी: संसार में दो समान चीजें नहीं हैं । जो आदमी कहता है दो चीजें समान बनाकर चलेंगे मैं समझता हूं वह बिल्कुल गलत सिद्धान्त लेकर चल रहा है । आर्थिक विषमता दूर होनी चाहिये लेकिन इतनी ज्यादा भी दूर नही होनी चाहिये जिससे आदमी जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है वह निराश हो जाए । अगर कोई आदमी अधिक परिश्रम करता है उसको भी उतना ही वेतन मिलता है जितना परिश्रम न करने वाले को मिलता है तो वह निराश ही होगा और आगे प्रगति नहीं कर सकेगा । जो परिश्रमी के लिये आगे बढ़ने का सवाल है वह खत्म हो जाएगा । आपको एक ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे किसी को बैचैनी अनुभव न हो । मैं एक उपाय बताता हूं वह यह कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो । मैं महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने बहुत दिन पहले इशारा किया था कि देश से आर्थिक विषमता को दूर करना चाहिए और इसके लिये बड़े उद्योगों के पास मत जाइये, लघु उद्योगों के पास जाइये । अगर आप छोटे-छोटे उद्योगों के पास जाएंगे तो आर्थिक विषमता उत्पन्न नही होगी । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । आप पंजाब के बटाला और लुधियाना नगरों में चले जाइये । वहां आपको घर-घर में छोटे-छोटे कारखाने मिलेंगे । इससे वहां पर बिल्कुल भी आर्थिक विषमता नहीं है । इसलिए मेरा कहना है कि लघु उद्योगों के द्वारा आप आर्थिक विषमता को दूर कर सकते है ।

अंत में आपने सामाजिक समानता की बात कही है। समाज में चार कारण है जिनके कारण असमानता पैदा होती है । एक तो जन्म और जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर । इसको दूर करना है तो किस तरह से दूर करना है, यह हमें देखना है। मै आपसे कहना चाहूंगा कि डंडे के जोर से यह कभी दूर नही हो सकती । कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार सामाजिक समानता को डंडे से और कानून से कभी नहीं ला सकेगी । सामाजिक समानता आ सकती है तो दो जगह से आ सकती है । राष्ट्र भी दो जगह से बनता है या तो माताओं की गोद और कोख में बनता है या स्कूल और कालेजों में उनके गुरुओं के चरणों में राष्ट्र का निर्माण होता है । उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि रशिया के अंदर क्रांति हुई और क्रांति के बाद कुछ ही सालों में रूस ने एक नया राष्ट्र पैदा कर दिया । वह सिर्फ स्कूल और कालेजों के बेसिस पर हुई । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि, अगर आपको सामाजिक समानता लानी है तो देश की शिक्षा को साधन बनाना होगा । शिक्षा को अनिवार्य बनाना होगा । रैजिडैशियल स्कूल और कालेज खोलने होंगे जहां पर राजा और रंक, गरीब और अमीर सब के बच्चे एक साथ पढ़ सकें । एक जैसे वस्त्र हों, एक जगह बैठ कर खाना खाते हों । तभी सामाजिक असमानता दूर हो सकती है । अगर आप शोर्ट कट सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते हैं तो शोर्ट कट उपाय भी है । एक ही इशारा गवर्नमेंट को कर सकता हूं ।

मैंने बहुत दिन पहले डा० श्रीमाली जब यहां पर शिक्षा मंत्री थे, उनसे कहा था कि आप एक काम कर दीजिये कि आप अन्तर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दीजिये। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे देश में जो छूत-छात, ऊंच-नीच जाति प्रथा की बुराई है वह अपने आप खत्म हो जाएगी। मैंने उन्हें यह भी सुझाव दिया था कि जो विद्यार्थी नौकरी के लिये कम्पीटेटिव परीक्षाओं में बैठते हैं उनके लिए आप यह शर्त लगा दीजिये कि जो अन्तर-जातीय विवाह करेगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कर दिया गया तो जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में आना होगा वे सब अन्तर-जातीय विवाह करेंगे और इस प्रकार से हमारे देश से सामाजिक असमानता दो वर्ष में ही समाप्त हो जाएगी।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में लोगों के लिए नौकरियों की मांग की गई है। मेरी प्रार्थना यह है कि आप नौकरी की मांग मत करिये। नौकरी के स्थान पर आप एक शब्द यह जोड़ दें--राइट टू वर्क। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट काम करने का अधिकार दे और अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे सकती है तो लोगों को बेकारी का भत्ता दे। आप नौकरी मत मांगिये। नौकरी के स्थान पर काम मांगिये। हमारे देश में कहावत है-उत्तम खेती, मध्यम वण्ज-निकृष्ट चाकरी भीख निदान। मैं तो चाहता हूं कि राइट टू इम्पलायमेंट के स्थान पर राइट टू वर्क होना चाहिए। जो बातें मैंने कही हैं, अगर सरकार उन सिद्धान्तों को लेकर अपना काम करेगी तो इससे देश का भला होगा और जो एक्सप्लोयटेशन होता है वह भी समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप इन सिद्धान्तों का पालन करेंगे तो देश के अन्दर सामाजिक और आर्थिक दोनों समानताएं ला सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं धन्यवाद।

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : Sir, while supporting the Resolution, I would like to express my gratitude and appreciation to the mover of this Resolution who has tried to highlight the basic problems and challenges before us. No doubt, Tyagiji has given almost a blanket solution for every economic problem according to his wisdom but really it is not so simple. These are some of the most difficult problems of our society. There is no doubt that the Government is conscious of the fact and, of late, special attention is being paid to meet these challenges.

Sir, I would like to mention here that to all such problems, there are three types of approaches : Academic approach which is more for academic purposes, an ideal approach which is difficult to achieve in the normal circumstances and a realistic approach. Now, let us cut across the realistic approach and do away with the idealistic approach because we have failed to achieve anything so far by the realistic approach. Thanks to the emergency, backed by the 20-point programme, a new awakening, a new hope and a new confidence and an entirely new atmosphere is there in the country and a complete transformation is taking place. Sir, I would personally like to confine myself to one part of this Resolution, and that is, right to employment or right to work as some of the colleagues have suggested. Now, apart from the general question of unemployment, I wish to highlight the problem of the weaker sections of the society, specially, the Scheduled Castes and the minorities. No doubt, Scheduled Castes have reservations in employment opportunities but much yet has to be done because they still have to get their due share in services or employment or other places to work.

May I also say that the Constitution of India adequately protects the interests and the fundamental rights of the minorities also ? This aspect has further been strengthened by the Directive Principles of State Policy. Apart from the safeguards enshrined in the Constitution, a number of supplementary safeguards have been agreed to at the national level. But Sir, with regret, I have to say that the fact remains that in the matter of employment opportunities, the scheduled castes and the minorities, including the Christians, have some real difficulties. For instance, I would like to mention about the Muslim community. Before 1947, we were about 10 per cent to the total population of the country. Today, our ratio

[Shri Khursheed Alam Khan]

is about 10.5 per cent to the total population of the country. Before 1947, our representation in the services was about 32 per cent. But will you believe me if I say that it is only 2 per cent today? How can anybody say that we should not ask for the right to employment or the right to work? What should we do otherwise? I would like to say to the Members opposite that we may have a sense of inferiority complex, but, we are not inferior in any sense. Sir, socialism is our way of life and we always cherish our values and principles under the inspiring leadership of our Prime Minister. Our Prime Minister, particularly for the minorities and the scheduled castes, is like a beacon light or a guiding star and is leading us towards our destiny. We have look to the welfare and progress of the people as a whole. No section of the society should be a millstone round our neck. Unless this is done, it will not be possible for the entire nation to progress and for the opportunities to be shared by the citizens of this country, whatever may be their faith, religion or culture. Sir, some time back, Shrimati Indira Gandhi described in this august House the concept of democracy as giving of the right to the people. I quote:

"By people we do not mean a section of the people; we mean all the people."

Similarly, in a recent speech, the Prime Minister said that the test of democracy is that it safeguards the interests of the minorities adequately. Now, we have to fulfil this; we have to achieve this objective. Please do not consider for a moment that I plead only for the minorities. I fully share your sentiments for those who are weak, down-trodden, disappointed, dejected or frustrated. Frankly speaking, the legacy of some of the problems of the minorities in the country is the remnant of a political insanity which grippled the entire country in the last phase of the independence struggle. But unfortunately, even after the birth of the new nation, we are faced with these problems and it is hightime that something is done about it.

Sir, when I plead for the minorities, I would like to quote here one of the distinguished Chairmen of this House, late Dr. Zakir Hussain. While addressing the Muslims, he said: 'A word to my Muslim brethren. Science and technology are transforming the world beyond recognition. No community can remain static or aloof in this world in a flux. You should not lose your dynamism and capacity for change and adjustment.' "If the community

4 P.M.

has the determination and capacity for hard work and the right attitude to it, it will advance materially and spiritually too. The Holy Quaran says, "Surely Allah changes not the condition of a people until they change their own condition'." I quote this only to say that unless we also make determined efforts to change our own condition and to share with our other brethren of the country their difficulties, their sorrow, their joy and their happiness, it would be difficult for us to be really true and worthy sons of this great and ancient land.

Sir, now it is time that we should forget and forgive the past, and this can be done only when we show a little more largeheartedness and by being more considerate towards each other.

Sir, much has been said about the economic condition of the people. Here I would like to mention one thing more. The minority community, apart from the difficulties in the services, apart from their employment opportunities, has one more problem. The minority community was having almost a sort of monopoly in various kinds of arts and crafts. The Muslim artisans have, by tradition, been the

exponents of certain historical arts and crafts transmitted through the generations from father to son. In centres like Delhi, Bhopal, Agra, Lucknow, Patna and Hyderabad, strangulated by the new commercial organisations and being unable to cope up with modern sophistication, these arts and crafts are slowly withering away into oblivion. If not anything else, Sir, something should be done at least to preserve this precious heritage, these precious arts and crafts are of the country, of which we are all proud because this is not a heritage which has come from outside. This is a heritage which we have built up and developed in this country.

Sir, while talking about sharing of the joys and sorrows and benefits of our countrymen, I would like to mention that we also feel very proud that for centuries the saints, scholars, poets, artisans and musicians of the minority community had inspired the life and thinking of our people and have made an immense, valuable and everlasting contribution, and whenever our people took the sword in their hand to defend the motherland, they had acted like Havildar Abdul Hamid. I assure you, Sir, there will be no dearth of Havildar Abdul Hamids if we are given an opportunity to prove our love of the motherland and to prove our sense of sacrifice and to give of our best in the service of our nation and our society.

Sir, as far as the right to employment or right to work is concerned, I agree, it cannot be the exclusive right of any particular society or any particular people. But, surely, the criterion for employment or the criterion for work should be economic backwardness. Frankly, economic backwardness should be the basis of such decisions and no other thing should be taken into consideration. We have seen in the past that economic backwardness has been given the least priority when such matters were considered and, therefore, it is necessary that we should change our attitude, we should change our approach and we should have a new look and a closer look at all such problems and take necessary action.

Before concluding, Sir, I would like to mention that Muslims, Christians and other minorities in this country are known for their backwardness apart from their illiteracy and other social problems which they have been facing.

But you would agree that they also need to play a part in the novel adventure of a new order, have a place of honour and dignity and full sense of participation. When they have full sense of participation, I assure you, Sir, they would give their very best and they would not be lagging behind their other colleagues and other citizens of this country.

Sir, in the glorious enterprise of re-building India and re-constructing a new society in this ancient land, let our perpetual guide be the brightest star, an epoch-figure, that looms magnificient over the nation of heroes I mean, Shrimati Indira Gandhi. We hope that under her leadership and guidance it would be possible for the entire nation, irrespective of caste, creed and colour, to march forward and reach the destination which Pandit Jawaharlal Nehru had declared between the night of 14th and 15th August, 1947—and that was the goal and destination of democracy, secularism and socialism. Given an opportunity, I am sure we will make our rich and ever-lasting contribution in this behalf.

Sir, Shri Tyagiji is unfortunately not here; I wish he were here because he understands Urdu. Before concluding, I would like to quote an Urdu couplet for him. It is like this:

मैं वह साफ ही बता दूं जो है फर्क मुझ में तुझमें,
तेरा दर्द दर्दे तन्हा, मेरा ग़म, ग़मे जमाना ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Shri Nripati Ranjan Choudhury wanted to speak in Bengali. He gave prior notice of it, so that we could make available the services of an Interpreter.

*SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY : Sir, today a national dialouge is going on in the country as to whether we can change the fundamental rights in the Constitution or not. At the same time the Hon'ble Prime Minister has given the twenty point programme to the nation. Both the Government and our Party are considering as to the manner in which the Right to Property impedes the economic progress of our country. Keeping this in view a thorough discussion is going on in the country as to the extent to which the Constitution should be amended.

The Resolution, moved by Shri Nathi Singh, is very timely. He has given us an opportunity to participate in the national dialogue regarding the proposed amendments to the Constitution. I, therefore express my heart-felt thanks to Shri Nathi Singh.

Sir, I heard the speech of the Mover of the Resolution with great attention, as also the speeches made by Opposition Members, particularly by Shri Bhupesh Gupta and Shri Om Prakash Tyagi, Shri Gupta pleaded for the abolition of the Right to property and with his usual vehemence attacked the Monopoly Capital. He did not go deep into the merits of the Resolution. Actually, the Resolution aims at adopting such a path as will remove economic and social disparties from our society.

Sir, you will also agree with me that simply by abolishing the Right to Property the disparity in wealth in society cannot come to an end. For removing economic disparity in society the people should be organised. They should come forward to participate in the struggle against the economic disparity. The economic equality cannot come without active participation of the people.

My friend Shri Tyagi has made a forceful plea for the retention of Right to Property in the Constitution. His plea is in tune with the policy of his party. But his speech reflected the inherent weaknesses of his party. According to him, retention of the Right to Property will lead to economic prosperity in the country. His panacea for the present economic stagnation is that individual ownership should be given its rightful place. But if we follow his remedy, we shall merely safeguard the economic interests of Tatas, Birlas and Goenkas. I do not understand how the interests of the exploited workers can be safe in the hands of these capitalists. They can never feel the industries, owned by these people, as their own.

Sir, the Government is contemplating to bring an amendment to the Constitution which will not allow the enforcement of Fundamental Rights to come in the way of implementing the directive principles as laid down in the Constitution.

Sir, the wealth belongs to the nation. Therefore, our ultimate aim is to allow the workers to participate in the management of industries. We cannot allow Tatas and Birlas to grab the lion's share of the wealth of the nation in the name of protecting individual ownership. We cannot allow laks of pavement dwellers to die in hunger.

Sir, Shri Tyagi referred to Democracy. I want to tell him that without Socialism true democracy cannot be established. So long as disparity in wealth remains in the country, the exploited massess can never impose their will upon the affluent sections of society under the present democracy. Ninety five per cent of our people are poor. The entire wealth of the nation is being enjoyed by only five per cent of our people. So the poor can never establish their democratic rights against the money power of five per cent.

The Resolution before us aims at abolishing individual ownership of property. It is a very reasonable proposal. The last part of the Resolution seeks to provide right to employment to the people. It is a

*Original speech in Bengali.

vital question on which economists of various countries expressed divergent opinions. I do not feel that simply by amending the constitution we can provide jobs to the people. For that necessary atmosphere in the country should be created. Nowhere in the world, whether it is a socialist country or a capitalist country, it has been possible to provide jobs to all the people. Therefore, inserting the Right to Employment in the Constitution will definitely create troubles in the country and when that trouble will go out of our hands, my friend, the mover of the Resolution, may plead for the abolition of that right.

Sir, the Resolution says :

> .....the economic policies should be so regulated as to remove social and economic inequalities and create maximum employment opportunities in the country.

It is, therefore, stated in the Resolution that maximum employment opportunities should be created. It does not mean that we should provide jobs to everyone.

Sir, the unemployment in the country is increasing at an alarming rate. So whatever might be the thinking of the Government on the proposed, amendments to the Constitution, the vital question of unemployment cannot be ignored. I would urge upon the Government to pay special attention to it.

Sir, our Labour Ministry has got statistics about the unemployed persons in the country. We have educated unemployed, uneducated unemployed and unemployed in urban and rural areas. Their respective figures are with the Labour Ministry. It should formulate an employment scheme coordinating factors like production, consumption and employment. The scheme should be a time-bound one. It should be implemented within a period of ten years. In this manner we can provide jobs to large number of people, particularly to those who are willing to work. If such a scheme is formulated by the government, the discussion on the present Resolution will not be necessary.

Sir, an atmosphere of discipline has been created in the country after the implementation of the Twenty Point Programme. Therefore, if the Government formulates an employment scheme, I believe that such a scheme will meet with success in the present disciplined atmosphere in the country.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Shri Parikh.

SHRI SARDAR AMJAD ALI (West Bengal) : I was the second speaker from this group.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : You are perfectly right. Your name was there as the second speaker. Since some members requested me that they had some urgent business . . .

SHRI SARDAR AMJAD ALI : If I had known this I would have adjusted my programme. I have some other appointment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : I will call you after he finishes.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : You should have called me. Thank you. I am not walking out. I have some other appointment.

SHRI D. P. SINGH (Bihar) : Before my turn comes, he must have precedence. I will forego my chance.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : My friend is always generous to me. The whole House is generous to me, I know. But I am not speaking. I will speak next time.

PROF. RAMLAL PARIKH (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, the Resolution moved by the hon. Member is before this House

[Prof. Ramlal Parikh]

and it contains two or three very important matters pertaining to our Constitution.

श्री गुणानद ठाकुर (बिहार) : अगले सप्ताह इस पर अगर बहस होगी तो मैं उस दिन बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : अगले सप्ताह तो नहीं 28 तारीख को इस पर बहस होगी।

श्री गुणानन्द ठाकुर . तो मैं इस पर 28 तारीख को बोलूंगा।

PROF. RAMLAL PARIKH : One is about the right to work. The hon. mover of the Resolution has worded it as "Right to Employment". I would rather prefer to call it "Right to work" which will be a wider term which will include right to employment, wherever possible. This is a very crucial matter and we are all exercised over it. In such a vast country like ours, with the rising population almost at the rate of 2.5 per cent and with millions of our people, particularly in the villages and in rural areas and that too particularly among the weaker sections of the society, remaining without work, without even adequate livelihood, without adequate sustenance, is a matter of great concern to all of us. I would, therefore, support this move to have the right to work included in the Fundamental Rights. If the spirit of our Constitution has to be translated into action, I think the State cannot escape the responsibility of ensuring right to work to everybody. By 'everybody' I mean every able-bodied man and woman. Anybody who has ability to work should be provided with work, whether such work is manual, semi-manual, intellectual, technical, semi-technical, professional or semi-professional. I would not go into that. The important issue is that unless this right to work is guaranteed to every man and woman, he or she will not be able to survive in this country with the rising figure of poverty, with the rising numbers of people who are below the poverty line. It is, therefore, a very welcome move.

And, Sir, I welcome it to the extent to which it relates to making the right to work a fundamental right. Now, the Reports of the various Ministries and the Departments of the Government of India indicate the rising figures of the educated unemployed. But we do not have any correct estimate of the uneducated unemployed. Even the figures of the educated unemployed are not necessarily correct. Even today morning, during the Question Hour, we were told that the number of the educated unemployed persons, registered with the Employment Exchanges in the country, rose from 41.75 lakhs on 31-12-1974 to 47.84 lakhs on 31-12-1975—so much increase in a period of one year. This is a phenomenal rise and this too is with respect to those persons who have registered themselves with the Employment Exchanges. But there are many more people, many many thousands, who are not on record and who have never seen the Employment Exchanges and who have never gone to the Employment Exchanges. There are thousands of people like the peasants and other agricultural workers in the rural areas who have no opportunity to get work and we have no estimates of their number at all. If we get the real estimates of the number of such people, it would actually be very alarming and frightening and we should really feel ashamed that in this country we have not been able to solve the problem of providing minimum work and minimum wages to everybody. Therefore, I feel that the time has now come when this right to gainful work should be included in the Fundamental Rights of our Constitution.

[The Vice-Chairman **(Shri Ranbir Singh)** in the Chair]

The next question that arises is the question of disparities. Disparities are rampant in this country and there are disparities of every kind. Disparities in income, disparities in wealth, disparities in opportunity, disparities in the means of livelihood, disparities in the matter of work are all there and they are very wide also. Now, Sir, we should make a beginning. First of all, reducing the disparities in income is a very important thing. The

Gujarat Government, during the Janata Front rule, took a very bold and progressive measure of reducing the disparities in income and tried to bridge the gap between the lowest and the highest income by reducing it from 1 : 20 to 1 : 10. It was reduced from 1 : 20 to 1 : 10. The lowest-salaried man in the Government and the Government-aided institutions would now earn about 270 rupees per month and the highest-paid man would get Rs. 2,700/- per month and this will come to much less if you take into account the income to be deducted.

SHRI IRENGBAM TOMPOK SINGH (Manipur) : I think you are excluding the Governor.

PROF. RAMLAL PARIKH : I am not speaking of the Governor now ; but I am speaking of the employees only. The Governor is not goverened by the State rules ; his pay is prescribed by the Constitution and settled by the Central Government. Now, Sir, the time has come for the Government to lay down for the whole country that the highest income of an individual will not be more than ten times that of the lowest-paid man. Actually, it should be even less and it should be 1 : 8 or 1 : 6 or 1 : 5 and that is what we should aim at. But we must make a beginning somewhere and we can keep the ratio at 1 : 10 now. Here also, Sir, I would not like to exclude the professions and the technicians and the technologists. In the name of science and technology, Sir, we have created a class of neo-capitalists and we have to guard ourselves against this. We would certainly encourage all our professional men and give them the maximum support. But we must also make everybody feel that in trying to provide everybody with equal opportunities as prescribed in the Preamble to our Constitution, we are also trying to see that nobody gets more than a particular share, whether it is in rent or whether it is in property or whether it is in urban income or whether it is in agricultural income. This criterion should apply everywhere and the maximum income should be limited. In the case of wealth, also the maximum should be prescribed.

Nowhere it should be left with loose ends. And, therefore, Sir, Mahatma Gandhi said as far back as 1909 in 'Hind Swaraj' that in this country the economic status of an advocate or a pleader or a lawyer and a barber would be the same. This, Sir, is a socialist society we should aspire for, that a lawyer and a barber will have the same economic status. Now, this you cannot do unless you start scaling down the higher incomes and also providing the right to work to weaker sections. And when I say 'weaker sections', again we have to provide work for whole year also. The difficulty is that nobody has got full year's work. Our peasants, our 'kisans' do not have a whole year's work. They have work for hardly three or four months. The landless labour has work hardly for two or three months in a year. We do not bother as to how they pass their time or how they live. This is another question. Therefore, the second problem, again, is that we must bring down the ratio of disparities drastically.

Sir, the next question comes about the enforcement of some of the Directive Principles which our Constitution has laid down, particularly Article 45 dealing with universal primary education, Article 46 dealing with protection of weaker sections and Article 47 safeguarding the weaker sections from being exploited because of liquor and other introxicant drinks. That is why we must ensure prohibition. These are the Directives laid down in our Constitution which we have to translate into action, and . . .

AN HON. MEMBER : What about the 20-point programme ?

PROF. RAMLAL PARIKH : Well, Sir, I have not opposed the 20-point programme. The question does not arise. But merely the 20-point programme is not going to be adequate. You have to go ahead. Here the question comes up, particularly of giving special attention to weaker

[Prof. Ramlal Parikh]

sections, particularly the Harijans, tribals and other backward classes and minorities. Here, again, Mahatma Gandhi said : Let us begin all our development, all our planning all our projects and programmes for India's progress from the last, unto the last, for which 'Sarvodaya' was his motto, and he had stated this to our great, revered leader, Jawaharlal Nehru, in a talisman. He said : Whenever you are in difficulty, just remember the poorest, the lowest, the most exploited man, and find out whether your measures are giving benefit to him. This is exactly what we have to ask. The question is whether all our plans are going to benefit them. And we all know that the 'have-nots' have not benefited in spite of 25 years of planning.

Now, Sir, coming to the question of the right to property . . . (*Time Bell rings*) .....I am just winding up.

This right to property again in the Constitution is only a right of maintaining property within the authority of law. It means that nobody should take away the right to property without the authority of law. I do not think our Constitution guarantees the right to property to anybody. Article 31C makes the position very clear that whatever may be your Fundamental Rights, if a property is to be acquired or requisitioned for a public purpose, then no law will be questioned in the court. Therefore, I think we have done a very important thing. We have taken a very progressive step and we should sustain and maintain it. I do not think that after that article the right to property has any meaning in the Constitution. Actually, it does not mean much. I would not be very particular whether it remains as a Fundamental Right or not. Even if it does not remain, it does not matter. But certainly, Sir, I would like a provision, for safeguarding the citizens, that no Government officer or nobody or no bureaucrat can take away any property without due process of law or without authority under law . . .

(*Time bell rings*)

Therefore, there has to be somewhere a provision that wherever the State allows a certain limited property, it will be allowed to be protected and not just expropriated without legal authority. If you can provide that, then you can certainly think of this.

Sir, I think that this is a good Resolution on the whole and I welcome it with the proviso that the word 'employment' should be amended and the words 'right to work' should be used and also the proviso that the right to property should be provided somewhere as a legal right. It need not necessarily be a fundamental right. Thank you Sir.

SHRI D. P. SINGH : Mr. Vice-Chairman, Sir, it has been a little amusing to hear my friend, Mr. Omprakash Tyagi, from that side who has conveniently disappeared. He was trying to put a veil. But one can tear off the veil and see the ugly face. What is surprising is his continued love for property. Although he says that he is not fond of property, yet property must be protected. Why should the property be protected ? If you have property, let their be competition to gain more property and to make more profit and that competition leads to capitalism. Even if capitalism alone survives, that is not so undersirable as to what capitalism leads to. Capitailsm leads to monopoly and exploitation. They are so wedded to this concept of property that their entire thinking is blurred. On our part, we are revolved to the view that the Constitution and the bulk of the Directive Principles are sacrosanct provided that the people are given opportunity to earn and to make their living. To that extent, if there are any impediments in the path of achieving this objective, then those difficulties must be removed and the Constitution must be streamlined so that our people can get justice, fairplay and fulfilment.

Sir, since democratic socialism is the avowed objective which we propose to achieve, we have to be clear in mind as to what that socialism means. We think

that shorn of verbiage and shorn of play of language, socialism means the pay packet which a person carries to his home and to his family at the end of the week. The fatness and the bulk of that pay packet depends on how many days in a week he is allowed to work. To that extent, it is the endeavour and the cherished desire of everybody that when a worker goes to work in farm or field or factory, he should not be turned back in distress. We have not conceived of a society and the fathers of this nation or the present rulers or the Prime Minister or the leader of the party have not dreamed of a society in which anybody should be starving or should go to bed with hungry stomach. In fact, the entire fabric and the entire structure that we have envisaged and the entire tone of the administration is to see that the working sections of our society, our toiling millions, our workmen, our agricultural labour, our industrial labour, our workers in fields, factories and shops and our workers in the little street corners or wherever they may be, may have a chance to work. In fact, to that extent, we have created the credit institutions. To that extent, even when the big business came in the way, we said that we will take over the credit institutions. Why? It was no desire of ours to crush any monopolist or any capitalist in this country because we do not believe in violence. Non-violence is our creed, non-violence is our means, and non-violence is our objective. But the idea was that even if we desire that a person should have work, how does that person achieve the task? He has no capital, he has no means to start an industry, he has no means to open a shop, he has no means to carry on any business. Even if he is a small vendor, he needs small capital, even if he is *rikshaw-walla*, he needs a rikshaw, and even a *taxi-walla* needs a taxi. In fact, a workman needs his tools. Therefore, to that extent, we nationalised the credit institutions, so that credit may be available, so that, by and large, whoever cannot get a Government job or employment anywhere by way of service, may be self-employed, may employ himself, and the State would provide the means on easy instalments. Not only this. When we felt that his power, his energy, his capabilities, his abilities were jeopardized because the man was in debt and his vitality could not be allowed to work up to a pitch, we said that his credit would be wiped off. This wiping off of the credit was not the wiping off of the debt of the Birlas or the Tatas and it was to wipe off the debt of the grumbling masses who could not raise their heads in spite of their best efforts. Year after year, their entire earnings, their entire savings used to be wiped off in paying the interest on loans taken from the greedy, hungry money-lenders. Therefore, to that extent, we have again made an effort and said, "No, from today onwards, you are a free man and you are free from debts."

Sir, another step we have taken is to remove the bonded labour. Somebody gave his forefather 30 or 40 rupees, and this man has been deprived of the liberty to choose his living. If his master is paying him 50 paise, in the neighbourhood he would get Rs. 1.50 or Rs. 2 or Rs. 5 as wages as is the prevailing market rate. He should not be deprived of that liberty because of his fore-fathers or he in his indiscretion or in a moment when he felt that he was not able to bargain, incurred the loan. The debt has crumbled his capacities. Therefore, to that extent, we removed the bonded labour and freed him and gave him the liberty to choose his master so that he can bargain for better wages, he can bargain and determine the price of his labour and the price of his effort. So, slowly and imperceptibly and many a time demonstrably also, this Party has been trying to achieve and secure for the millions better conditions of work. By and large, our young children, our growing children are getting more and more education, and more and more technical know-how, so that not only in India but in the world over, they can go and compete. Sir, we are really proud and happy that our men are digging the deserts in far off places in search of oil. India is

[Shri D. P. Singh]

providing the technical know-how to so many countries. Our young men who have received technical education are trying to dig wells in Iraq, in Libya, in Tanzania and in other distant places, and trying to secure oil for those countries so that this country also may have a share in it. Our technical skill is growing fast. It is heartening that atomic secrets are no longer a secret for a few, no longer a preserve of a few. It is the skill that this country provides going in far distant places like Southern America, like Argentina and other places in Africa where our men are giving technical education, technical training and our men are employed in larger numbers so that they receive this training from us. Therefore, Sir, all these steps we are taking in the same direction in which this Resolution is framed, that there must be a right of employment. Right of employment does not arise merely by putting it in the Constitution. Naturally, it may be put in the Constitution as a Fundamental Right; it may be a welcome feature but even without putting it, Sir, I say that this country has been moving along this path. The great visionary, Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation of the various technical institutions in this country, when great men from other countries came and said: "Why are you dependent on America ?" I remember Mr. Khruschev came and talked to Pandit Jawaharlal Nehru and asked: "Why are you relying on America for this and for that?" And Pandit Jawaharlal Nehru replied: "My dear Mr. Khruschev, from pin to aeroplane, we can manufacture nothing in this country." Such had been the tragic situation of these great people where the expertise was great at one time and the things that were produced in this country would go across the seas 400 years before. Today it is pathetic that in the technological world, we are not having anything and it was as a result of this, that various institutions in collaboration with the Soviet Union and other countries grew one by one. Other countries like Germans and thereafter British also collaborated and that was the foundation laid of educating our children, our people towards the scientific world. When Pandit Nehru used to have a discussion with the great master, Mahatma Gandhi, it was not as though the paths were different. But, Pandit Nehru was a modern man and he found that in spite of the goodwill, in spite of what this country was able to do, if we are not able to pull our people out of the bullock-cart age, then the going to the moon will remain a distant dream, will remain merely a dream that we have read in *Maha Bharata* and that may not be possible for us to accomplish. And he wanted to translate this dream into reality. Therefore, Sir, great institutions were created by Pandit Jawaharlal Nehru, like the Heavy Engineering Corporation of Ranchi. People said that this is a dream, a wild dream of that stupid man, the wild dream of that mad man. Sir, do you know what we are manufacturing in the Heavy Engineering Corporation ? We are able to cast steel up to 130 tonnes. Sir, you would be surprised to know that the maximum tonnage cast in Europe, minus the Soviet Union, in France and in England is 30 tonnes. Our capacity is 130 tonnes. And that was the dreamer who dreamt that if we have to put this country on the map of the developed nations, if we have to match them in their ability and in the scientific development, we have to go on scientific lines. Therefore, he laid the foundation so that our people may learn the science, may learn the technology, may learn the technique to counterbalance the economic forces that have killed us and robbed us. Sir, you know very well the misfortune of the farmers in this country. Not long ago, Sir, within our living memory, one brush, one packet of tooth-paste used to cost as much as a maund of rice. This was the position in the country. This was because our people were not able to manufacture goods. Earlier, the prices of raw materials in the Asian, African and Latin American countries used to be very cheap and the prices of the finished products tremendously high

In fact, many a time, in many cases, it continued to be the same. Only in 1950, in Iran, Mr Mossadiq declared 'The soil is ours; the oil is ours' and the first attempt was made to nationalise the industries. These forces combined to constitute the biggest force. Now, they are dictating the prices against the mightiest and the biggest of forces. Everybody is crumbling before them. All the big countries are bowing down before the power of the developing countries. Such is the value of technology and such is the value of unison of strength. Sir, we, on our part, welcome such a change. It would be a great day when every person in this country would be assured of employment and when every person, when he goes back home, carries a packet that gives satisfaction to him and to his family. To that end, our Constitution, all the limbs of our Constitution, the Executive, the Judiciary and the Legislature, are bending their energies and we are looking forward to this happy day. I sincerely hope that this day would come sooner than later.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate Shri Nathi Singh, for bringing forward this Resolution. This is a very good Resolution. Firstly, Sir, this Resolution seeks to delete the right to property from the Constitution. Secondly, it wants that the right to employment should be inserted in the Constitution.

As far as the right to property is concerned, we are already complaining that the bureaucracy is overriding the Legislature and the parliamentarians. If we take such a step at this stage, if we delete the right to property from the Constitution we will be greatly increasing the jurisdiction of bureaucracy we would have to carry on our own shoulders the task of looking after the welfare and subsistence of the 60 crores of our people. It is not workable at present. It may be workable in some future times. In principle, it is a very good idea. But at present, it is not workable.

Secondly, it is a very good step towards socialism. Before taking a socialistic step, we have to think how far we are socialists ourselves. How far the 60 crores of our people are socialistic? Socialism does not mean that we should nationalise the property. But we should think whether we are dedicated to the society and how many of us think in terms of the society rather than the self. If we are not socialists ourselves, it would be very difficult to make the entire country socialistic. What I have to say in this connection is that we can restrict it, in principle, but we cannot totally delete it. It is desirable that we should do something to restrict unlimited holding of properties by people.

Now there is a general feeling among the people in the rural areas that Government has taken lands from them but it is not doing anything for limiting the extent of properties in the cities. I think this is a very reasonable thing because when we could take lands from the rural people, why not we do something about limiting the properties in the cities? So far as lands are concerned, perhaps the Government thinks that because grains are produced on the land, land could be a sort of factory for producing grains.

I feel that we have been unreasonable in one thing. We had not gone to the extent of giving a reasonable price to the owners of the land from whom we took land. The land-owners reasonably deserve a fair price and they should have been given that. Had we done it, the ill-feeling among the villagers that Government had taken away their land would not have been there. If we had paid a reasonable price to them, there would have been no problem. After all, when we take over factories, we pay a reasonable price to their owners. Similarly, my personal thinking is, we should have paid a reasonable price to the land-owners also.

Now, these rural people say that the properties in the cities should be limited. That is a reasonable thing. The properties should be limited to a certain extent

[Shri Jagan Nath Bhardwaj]

though the work involved might be difficult and complicated. But something in this direction is essential at any cost. We have taken land from people and now there is no trouble about it. What is done is done. But now, for the satisfaction of the rural people, it is equally desirable that something to limit the size of properties in the cities must be done immediately, if not remove wholly the right to hold property. But I personally feel it is rather difficult to delete it totally as moved in the resolution of my hon. friend.

Anyway, to put it in a nutshell, at this stage we cannot afford to totally delete the right to property from the Constitution, but we should do something certainly about it and there should be some limitation on the property other than agricultural land, wherever it is. The right to keep such property should be limited to a reasonable extent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Would you like to continue on the next day?

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP (Maharashtra): That has been announced.

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Only for Government Business.

AN HON. MEMBER: We can sit beyond 5 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): No.

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP: That is your discretion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): That is the decision of the House, as per the recommendation of Business Advisory Committee.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Why?

5 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): Discussion on the Resolution will go on on the 28th. You may continue on the next day.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 17th May, 1976.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 17th May, 1976.

MGIPRRND—RSS/76—III—D—1-7-76—595